

मोपाल

24 अक्टूबर 2026

शनिवार

आज का मौसम

 33.2 अधिकतम

 15.6 न्यूनतम

डाक पंजीयन क्रमांक: म.प्र./4-474/2024-26

बेबाक खबर हर दोपहर

दोपहर मेट्रो



Page-7

राहुल गांधी को गिरफ्तार क्यों नहीं कराते मोदी-शाह?

राहुल गांधी पर संगीन आरोप लगाने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके खिलाफ



प्रसंगवश

राजेश सिरोटिया

कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? मोदी-शाह की तो छोड़िए, भाजपा का कोई दूसरा नेता उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराता? आखिर क्या वजह है कि आरोपों की बौछार करने वाली भाजपा कानूनी कार्रवाई के सवाल पर अक्सर मौन साध लेती है?

न्यूज टिंडो

जम्मू के पुंछ में भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने से मचा हड़कंप
पुंछ। जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती पुंछ जिला में सुरक्षा बल ने एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाकर आतंकी ठिकाने से सात कंटेनर में विस्फोटक सामग्री बरामद की। टेप से लिपटे कंटेनर में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल जांच जारी है। पिछले 10 दिन में पुंछ और राजौरी जिलों में चार बार हथियार और गोलाबारूद बरामद हो चुका है। हालांकि ये सभी हथियार पुराने बताए जा रहे हैं।

भागवत 3 दिन जबलपुर में कार्यकर्ताओं से कर रहे संवाद
जबलपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत आज से 3 दिन जबलपुर प्रवास पर है। 26 अक्टूबर तक वे संघ के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान दायित्ववान कार्यकर्ताओं, महाविद्यालयीन स्वयंसेवकों और संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ संवाद और बैठक करेंगे। प्रवास के पहले दिन आज भागवत जबलपुर महानगर में निवासरत मुख्य शिक्षक और उनसे ऊपर के दायित्ववान कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। इस दौरान संगठनात्मक कार्यों से जुड़े विषयों पर चर्चा कर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

पेड़ से टकराई बोलेरो, सेना के जवान की मौत, पांच घायल
केशकाल। छत्तीसगढ़ के केशकाल इलाके में गड्डीपलना मोड़ के नजदीक एक बोलेरो कार सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। दुर्घटना में सेना के एक जवान की जान चली गई, जबकि कार में सवार दूसरे सैन्य जवान सहित पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक, दुर्घटनाग्रस्त बोलेरो में सवार सभी लोग ग्राम पल्ली के निवासी बताए गए हैं। देर रात करीब दस बजे ग्राम पांडे आठगांव जा रहे थे। जैसे ही उनका वाहन गड्डीपलना मोड़ के घुमावदार रास्ते पर पहुंचा, बोलेरो अचानक अनियंत्रित हो गई और सीधे एक बड़े पेड़ से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और अंदर बैठे लोग गंभीर चोटें आईं।

आज का कार्टून

यूपी चुनाव: बीजेपी काट सकती है अपने सिटिंग विधायकों के टिकट



सहानुभूति देकर राजनीतिक हीरो नहीं बनाना चाहती भाजपा!

बीजेपी शायद नहीं चाहती कि राहुल गांधी को जेल भेजने की किसी कार्रवाई से उन्हें जनता की निगाह में सहानुभूति का पात्र बनने या राजनीतिक हीरो के रूप में उभरने का मौका मिले । राहुल गांधी भी संभवतः भाजपा की इसी दुविधा को समझते हैं। इसीलिए वे आक्रमक बयानबाजी और गुरिल्ला युद्ध जैसी रणनीति अपना रहे हैं । कभी आकाशवाणी तो कभी सुप्रीम कोर्ट परिसर में प्रवेश इसी पूर्व नियोजित पटकथा का हिस्सा है । मकसद बीजेपी को उकसाने का है । उनका प्रयास है मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री साबित करना और संवैधानिक संस्थाओं के भाजपा से घालमेल का नैरेटिव बनाना । भाजपा के सामने बुनौती यह है कि वह राहुल के आरोपों का जवाब देते हुए उन्हें ऐसा राजनीतिक अवसर न दे, जिससे कांग्रेस अपने विरोध अभियान को सहानुभूति की लहर में बदल सके। इतिहास गवाह है कि राहुल गांधी की दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सत्ता और राजनीतिक विरोध के टकराव में कठोर फैसले लिए थे। 1975 में आपातकाल लागू करने और विपक्षी नेताओं को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार कराने के उनके फैसले ने भारतीय लोकतंत्र पर गहरी छाप छोड़ी। अंततः 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी। आज उसी कांग्रेस को लोकतांत्रिक संस्थाओं और राजनीतिक स्वतंत्रता के सवाल पर भाजपा को बुनौती देते देखना भारतीय राजनीति का एक दिलचस्प विरोधाभास है। दूसरी ओर, भाजपा भी शायद इंदिरा गांधी के दौर की गलतियों को दोहराने से बचना चाहती है। वह राहुल गांधी के आरोपों का जवाब राजनीतिक मंचों से देकर और उनके रवैये पर सवाल उठाकर मुकाबले को चुनावी विमर्श के भीतर रखना चाहती है।

जबकि कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता खुलेआम भाजपा को राहुल को गिरफ्तार करने की चुनौती दे रहे हैं। इसके प्रमुख प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और संबित पात्रा इसे प्रधानमंत्री मोदी की उदारता का प्रतीक बताकर कांग्रेस के सवाल को चतुराई से टाल जाते हैं। एक बार दिल्ली के कुछ पत्रकारों ने भाजपा के एक नेता से पूछा था कि राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ताक पर रखकर बयानबाजी करते हैं, तो भाजपा उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? उनका जवाब दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो भी बोलते हैं, उस पर देश की जनता खुद संज्ञान लेती है। ऐसे में भाजपा को कुछ करने की जरूरत ही क्या है? इस जवाब में भाजपा की राजनीतिक रणनीति का एक अहम संकेत छिपा था। अब जबकि राहुल गांधी के बयान और विरोध के तरीके राजनीतिक टकराव को लगातार तीखा कर रहे हैं, तब भी भाजपा कानूनी कार्रवाई के बजाय राजनीतिक मुकाबले को प्राथमिकता देती दिखाई दे रही है। खासकर सोशल मीडिया पर विवादित बयानों और अभियानों को लेकर चल रही राजनीतिक खींचतान में कांग्रेस ने इस टकराव को और हवा दी है। काकरोच पार्टी के कार्यकर्ताओं और वामपंथी संगठन 'आइसा' से जुड़ी नेहा वोरा को अपने साथ बताने पर बीजेपी कांग्रेस को घेरने के मौके के बतौर देख रही है। भाजपा चाहे तो उपलब्ध तथ्यों और लागू कानूनों के आधार पर कानूनी विकल्पों पर विचार कर सकती है। लेकिन उसकी रणनीति फिलहाल बयानबाजी, राजनीतिक लामबंदी और सड़कों पर मुकाबले तक सीमित दिखाई देती है। लोकतंत्र में किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई राजनीतिक आरोपों के आधार पर नहीं, बल्कि उपलब्ध साक्ष्यों और कानून के आधार पर होनी चाहिए। इसी तरह, किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई न होना अपने आप में उसकी बेगुनाही या सरकार की कमजोरी का प्रमाण नहीं है। हालांकि वक्त ही बताएगा कि संसदीय गरिमा और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर राहुल गांधी तथा कांग्रेस का टकराव किस मुकाम तक पहुंचेगा। राहुल गांधी को इससे कितना राजनीतिक लाभ मिलता है और भाजपा को कितना नुकसान होता है, इसका निर्णायक आकलन अगले

मिसरोद से बैरागढ़ चीचली जाने वाली मास्टर प्लान रोड को बीच में ही रोका ऐसे बदलेंगे मास्टर प्लान के प्रस्ताव तो टूट जाएगा निवेशकों का भरोसा

मोपाल, दोपहर मेट्रो

भोपाल के बहुप्रतीक्षित मास्टर प्लान 2047 के ड्राफ्ट पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का आज आखिरी दिन है और लोग रात 12 बजे तक ऑनलाइन या ऑफ लाइन अपनी बात रख सकते हैं। दावे और आपत्तियों के बीच मास्टर प्लान के प्रस्ताव बार - बार बदले जाने से शहरी विकास से जुड़े विशेषज्ञों में असंतोष है। उनका कहना है कि इससे शहर में निवेश करने वालों का भरोसा टूटता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिसरोद से बैरागढ़ चीचली तक जाने वाली रोड है जिसे सोहागपुर गाँव के पास रोका जा रहा है, जो कि किसी भी तरह व्यवहारिक नहीं है। प्रस्तावित मास्टर प्लान 2023 के मसौदे में फेरबदल करके नए प्रारूप में मिसरोद से बैरागढ़ चीचली तक जाने वाले मास्टर प्लान रोड को बीच में ही रोक दिया गया है। इसे पहले ग्राम हिनोतिया आलम और बिलखिरिया खुर्द की सीमा से निकलने वाले 24 मीटर रोड को सोहागपुर ग्राम की सीमा से आगे आगे बढ़ाते हुए देहरी कलॉ, कांकरिया , इनायतपुर ,कोलार सिक्स लेन से रसूलिया जागीर तक जोड़ने का प्रावधान था। रसूलिया जागीर से सतगढ़ी तक प्लान में पूर्व से ही 24 मीटर रोड प्रस्तावित है। सोहागपुर से रसूलिया जागीर तक सड़क को आगे बढ़ाने से मिसरोद से सतगढ़ी औद्योगिक क्षेत्र तक सीधे कनेक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन नए प्लान से विकास योजना का मसूबा धरा का धरा रह गया है। वर्षों से शहरी विकास के विमर्श से जुड़े रहे विशेषज्ञ मानते हैं कि नए मास्टर प्लान के साथ नीतियों में निरंतरता और निवेश की सुरक्षा भी जरूरी है। वर्ष 2020 में प्रकाशित योजना 2031 के प्रारूप पर प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए शासन ने 2023 में नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(2) के तहत बदलाव प्रकाशित किए थे। दशकों से नए मास्टर प्लान और लैंड यूज व प्रस्तावित सड़कों की स्पष्टता का इंतजार कर रहे निवेशकों ने इस प्रारूप और मानचित्रों को आधार बनाकर इन्वेस्टमेंट किया था किया। अब 2047 के प्रारूप में कई पुराने लैंड यूज और प्रस्तावित मार्ग बदलने या हटाने से उनके निवेश और परियोजनाओं के भविष्य पर सवालिया निशान लग गया है। जो लोग भी मास्टर प्लान के पुराने ड्राफ्ट को देखकर निवेश करते हैं, उन्हें प्रस्ताव बदलने पर भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है। इससे बाहरी और स्थानीय निवेशक शहर में बड़ी पूंजी लगाने से कतराने लगते हैं।

मिसरोद से सतगढ़ी औद्योगिक क्षेत्र तक सीधे कनेक्टिविटी पर असर दावे-आपत्तियां दर्ज कराने का आज आखिरी दिन



कोलार रोड पर कम हो सकता है वाहनों का दबाव

कोलार रोड अभी सिक्स लेन जरूर है लेकिन वाहनों का अभी से इतना दबाव है कि दोनों तरफ पार्किंग के बाद यह फोरलेन ही रह जाता है। यदि मिसरोद - सलेया से होते हुए सोहागपुर से अस्सी फुट का रोड डेहरी कलॉ होते हुए निकलेगा तो कोलार रोड पर दबाव कम होगा, क्योंकि लोगों को वैकल्पिक मार्ग भी मिल सकेगा। लेकिन, इसे सोहागपुर तक रोकने से सारा उद्देश्य ही परास्त हो गया है। क्रेडॉई भोपाल के अध्यक्ष मनोज मीक का कहना है कि बार बार प्रस्ताव बदले जाने से निवेशकों के भरोसे पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उन्होंने माँग की है कि विकास योजना 2031 के धारा 19(2) में प्रकाशित उपांतरणों सहित लैंड यूज और प्रस्तावित मार्गों को नई योजना में यथावत रखा जाए। जहाँ कानूनी तौर पर पर्यावरण या व्यापक जनहित में बदलाव जरूरी हो, वहाँ उसका स्पष्ट कारण सार्वजनिक किया जाए।

भारत का मोस्ट वॉन्टेड गैंगस्टर हिमांशु भाऊ अमेरिका में गिरफ्तार, 30 से ज्यादा मामलें दर्ज नई दिल्ली। भारत के मोस्ट वॉन्टेड गैंगस्टर हिमांशु भाऊ को अमेरिका में एफबीआई ने गिरफ्तार किया है। हिमांशु पर दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में मर्डर, हत्या की कोशिश, रंगदारी और हथियारों की तस्करी जैसे करीब 30 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी सामने आई है। इंटरपोल ने उसके खिलाफ 2023 में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। हरियाणा पुलिस ने उस पर 2.5 लाख और दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। 2022 में हरियाणा में 24 घंटे में तीन हत्याओं के बाद हिमांशु चर्चा में आया था। हिमांशु भाऊ की गैंग ने ही 2025 में यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर के बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। हिमांशु की लॉरेंस और गोल्डी बराड़ गैंग से दुश्मनी मानी जाती है।

भोपाल में राष्ट्रीय एचआर-सीएसआर सम्मेलन

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि शासन में मिले पद को जिम्मेदारी से निभाना और वचन देने के बाद उसे पूरा करना भगवान श्रीकृष्ण के जीवन से सीखने योग्य संदेश है। श्रीकृष्ण ने कंस का वध किया और महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया, लेकिन खुद सत्ता नहीं संभाली। मुख्यमंत्री आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में चतुर्थ राष्ट्रीय एचआर-सीएसआर सम्मेलन 'अभ्युदय-2026' के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि श्रीकृष्ण ने यशोदा माता के हाथ से ही

मुख्यमंत्री बोले-पद को जिम्मेदारी से निभाना श्रीकृष्ण से सीखें, माता को दिया वचन निभाया



माखन खाने का वचन दिया था और उसे निभाया। उनके जीवन की ऐसी घटनाएं बताती हैं कि वचन का पालन कितना महत्वपूर्ण है।

राज्य में 97% लोग मांसाहारी

केरलम राज्यपाल ने पद संभालते ही लोकभवन में नॉनवेज पर रोक लगाई

तिरुवनंतपुरम। केरलम के नए राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर के पद संभालने के कुछ घंटे बाद ही लोकभवन में मांसाहारी खाना बनाने और परोसने पर रोक लगा दी गई। कांग्रेस और विपक्षी CPI(M) ने इस फैसले की आलोचना की है। कांग्रेस ने कहा कि क्या अब राज्यपाल तय करेंगे कि क्या खाना है!राज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने कहा कि माथुर शाकाहारी हैं। इसी वजह से उन्होंने यह बदलाव कराया। सूत्रों ने साफ किया कि लोकभवन के कर्मचारियों के खाने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। माथुर ने कल सुबह केरलम के 29वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सीमेन सेन ने उन्हें पद की शपथ दिलाई थी। केरलम में 97% लोग मांसाहारी हैं।

कांग्रेस बोली- राज्यपाल ने हद्द पार कर दी

AICC महासचिव और अलप्पुझा लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सिर्फ शाकाहारी खाना बनाने का निर्देश देकर राज्यपाल ने हद्द पार कर दी है। उन्होंने कहा कि केरलम की खान-पान की संस्कृति अलग है। तटीय राज्य होने के कारण यहां मछली भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। राज्य के लोग शाकाहारी या मांसाहारी भोजन चुनने के लिए स्वतंत्र हैं।

ट्रम्प बोले-हमले के लिए तैयार रहे, ईरान ने कहा इंटरनेट केबल काट देंगे

वॉशिंगटन डीसी/तेहरान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के खिलाफ फिर सैन्य कार्रवाई करने की धमकी दी है। उन्होंने नपलोरिडा में एक रैली के दौरान कहा, 'हम एक और छोटा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कर सकते हैं।' अमेरिकी सेना ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ शुरू हुए युद्ध को 'एपिक फ्यूरी' नाम दिया था। हालांकि, ट्रम्प ने यह नहीं बताया कि दोबारा सैन्य कार्रवाई कब या किस तरह की होगी। वहीं, ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने दोबारा हमला किया तो वह खाड़ी देशों में समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल को निशाना बनाएगा। इससे इंटरनेट सेवाओं, बैंकिंग और ऑनलाइन कारोबार पर असर पड़ सकता है।

तारीख बदलने की मांग

दिल्ली के कारोबारी राहुल से बोले-1 नवंबर को रैली न करें, करोड़ों का नुकसान होगा

दिल्ली, एजेंसी। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से इंडिया ब्लॉक की रैली टालने की अपील की है। सीआईटी ने आज पत्र लिखकर कहा कि 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली 10 नवंबर के बाद की जाए। संगठन ने दिवाली फेस्टिवल सीजन में 10 हजार करोड़ रुपए के व्यापारिक नुकसान की चेतावनी दी है। दरअसल, 1 नवंबर को रामलीला मैदान में सेंट्रल दिल्ली और ज्ञानेश कुमार के विरोध में इंडिया ब्लॉक की रैली है।रामलीला मैदान के 5 किमी के दायरे में चांदनी चौक और कर्नाट प्लेस समेत 8 बड़े बाजार हैं।

धनतेरस पर 25 हजार करोड़ का व्यापार

दिल्ली में धनतेरस, दीपावली और भैया दूज के दौरान सोना-चांदी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और ऑटोमोबाइल समेत विभिन्न सेक्टरों में करीब 25,000 करोड़ रुपये का व्यापार होता है। 1 नवंबर से लोग खरीदारी शुरू कर देते हैं, जो दिल्ली की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है। सीटीआई के अनुसार, अक्टूबर में सेंट्रल दिल्ली में हुए प्रदर्शनों और रास्ते बंद होने के कारण व्यापारियों को पहले ही 3,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है।

गुलाबी ढंड की आहट



तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव, मौसम शुष्क, धार और इंदौर जिलों में हल्की बारिश

भोपाल। दोपहर मेट्रो

प्रदेश में गुलाबी ढंड की आहट के साथ तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। गुरुवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहा, जबकि धार और इंदौर जिलों में हल्की वर्षा हुई। धार में चार मिलीमीटर और इंदौर में एक मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रीवा में रात सबसे ठंडी रही, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 15.0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इसके अलावा उमरिया में 15.4 डिग्री और सीधी में 16.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम पारा दर्ज किया गया।

पचमढ़ी में दिन सबसे ठंडा खजुराहो में पारा 34.2 डिग्री पार

वहीं, नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में दिन सबसे ठंडा रहा, जहां अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। दूसरी ओर, छतरपुर जिले के खजुराहो में दिन का

पारा सबसे अधिक 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद गुना और रतलाम में 34.0 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। राजधानी भोपाल में दिनभर तीखी धूप निकली, जिससे गर्मी और उमस से लोग परेशान हुए। उमरिया में सुबह के समय में आर्द्रता 90 प्रतिशत और बालाघाट जिले के मलांजखंड में 87 प्रतिशत तक पहुंच गई, जिससे सुबह हल्की धुंध और ठंडक का असर देखा गया।

अगले 5 दिन शुष्क रहेगा मौसम 5 जिलों में हल्की वर्षा के आसार

मौसम विज्ञानी प्रमोद कुमार ने बताया कि अगले पांच दिन प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा। इससे अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री की गिरावट की संभावना जताई गई है। शुक्रवार को अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर में हल्की वर्षा हो सकती है।

खरीदी में गड़बड़ी पर 138 अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई, 38 अधिकारियों से वसूली के आदेश

मप्र के नगरीय निकायों में वर्ष 2023 से अब तक हुई खरीदी के विश्लेषण के बाद कार्रवाई की गई है। 7 कर्मचारियों की सेवा समाप्त की गई, 76 की वेतनवृद्धि रोकी गई और 17 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से वसूली का निर्णय लिया गया।

भोपाल। दोपहर मेट्रो

प्रदेश के नगरीय निकायों में खरीदी में गड़बड़ी की बात सामने आने पर सरकार ने उच्च स्तरीय जांच करने का निर्णय लिया है। वहीं, अभी तक 62 मामलों में अधिकारी-कर्मचारी जांच के घेरे में आए। 7 कर्मचारियों सेवा समाप्त की जा चुकी है तो 76 की वेतन वृद्धि रोकी गई। 17 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से वसूली करने का निर्णय लिया गया है। 38 अधिकारियों से वसूली के आदेश दिए गए हैं। वहीं, 22 कर्मचारियों को जांच में आरोप प्रमाणित नहीं होने पर दोष मुक्त किया गया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने विभाग अधिकारियों की कार्यशाला में नगरीय निकायों में होने वाली वित्तीय अनियमितताओं को रेखांकित किया था।

प्रदेश के 500 से ज्यादा छात्र वाले कॉलेजों में बनेंगी एंटी-ड्रग समितियां

भोपाल। दोपहर मेट्रो

मध्यप्रदेश को मादक पदार्थों से मुक्त बनाने के लिए राज्य शासन के अनेक विभाग संयुक्त अभियान चलाये और शुरुआत में 500 से अधिक विद्यार्थी वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षक, पालक, विद्यार्थी, उच्च शिक्षा, सामाजिक न्याय विभाग तथा पुलिस को समाहित कर एंटी ड्रग समितियों का गठन किया जाएगा। मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल मंत्रालय में पांचवी राज्य स्तरीय एनसीओआरडी बैठक में समीक्षा कर रहे थे। पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना सहित अनेक विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष नार्कोटिक्स और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। मुख्य सचिव श्री बर्णवाल ने



बैठक में कहा कि जिस प्रकार प्रदेश में नक्सलवाद को समाप्त किया गया है उसी प्रकार आगामी दो तीन वर्षों में अवैध मादक पदार्थों के संपूर्ण रैकेट को खत्म करने के लिए संबंधित विभाग गंभीरता पूर्वक ऐसा अभियान चलाए जिसका समाज के सभी वर्गों तक सपष्ट संदेश जाए। सभी विभाग त्रि-वर्षीय विशेष अभियान के लिए अपने आंतरिक लक्ष्य निर्धारित कर कार्य-योजना बनायेंगे। मुख्य सचिव ने ड्रग नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सूचना तंत्र को सद्गढ़ करने के साथ ही बेहतर समन्वय करने के निर्देश दिए।

भोपाल को कारखानों के साथ कार्गो सुविधाओं की भी दरकार - क्रेड्राई

भोपाल। दोपहर मेट्रो

क्रेड्राई भोपाल ने राजधानी में कार्गो सुविधाएं बढ़ाने और औद्योगिक विकास पर ध्यान देने की जरूरत बताई है। क्रेड्राई के अनुसार राजा भोज विमानतल से अप्रैल से अगस्त 2026 के बीच 996.6 टन घरेलू हवाई माल की ढुलाई हुई। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पांच मासिक दस्तावेजों के तुलनात्मक अध्ययन के अनुसार, इसी अवधि में इंदौर से 4,553.8 टन माल की ढुलाई दर्ज की गई। यानी इंदौर की तुलना में भोपाल से करीब 4.6 गुना कम माल भेजा गया। राजधानी में कार्गो सुविधाओं और औद्योगिक विकास पर ध्यान देने की जरूरत बताता है।

मध्यप्रदेश के निवेश पोर्टल पर भोपाल और इंदौर में बहु-माध्यम लॉजिस्टिक्स पार्क प्रस्तावित बताए गए हैं। वहीं, केंद्र सरकार ने एक अप्रैल 2026 को राज्यसभा में देश के 15 प्राथमिकता वाले लॉजिस्टिक्स पार्कों की जानकारी दी



थी। इनमें इंदौर का नाम शामिल है, जबकि भोपाल का उल्लेख नहीं है। दोनों योजनाएं अलग हैं, लेकिन राज्य सरकार को भोपाल की परियोजना की जमीन, मंजूरी और बजट की स्थिति भी साफ करनी चाहिए। राजा भोज विमानतल पर घरेलू कार्गो टर्मिनल 2023 में शुरू हुआ था। पश्चिम मध्य रेलवे की 2023-24 की रिपोर्ट में मंडीदीप कंटेनर डिपो और पवारखेड़ा सहित अन्य माल ढुलाई केंद्रों का भी उल्लेख है। इन सुविधाओं को आसपास के

औद्योगिक क्षेत्रों से बेहतर तरीके से जोड़ने की जरूरत है। क्रेड्राई भोपाल के अध्यक्ष मनोज सिंह मीक के नेतृत्व में 'कमाल का भोपाल' अभियान राजधानी को बड़ा लॉजिस्टिक्स केंद्र बनाने की पैरवी करता रहा है। मीक के अनुसार, अब सवाल यह नहीं होना चाहिए कि पहले कारखाने बनें या कार्गो हब। उद्योगों को सस्ती ढुलाई चाहिए और कार्गो केंद्रों को नियमित माल। मंडीदीप, औबेदुल्लागंज, तामोटा, बुदनी, मोहासा और बाबई जैसे औद्योगिक

योजना बनाकर बढ़ने की जरूरत

औद्योगिक विकास निगम को उपलब्ध जमीन, बिजली, कुशल श्रमिकों और नए उद्योगों की जरूरत का आकलन करना चाहिए। विमानतल प्राधिकरण, रेलवे और उद्योग संगठनों को मिलकर माल की मात्रा, ढुलाई लागत और सुविधाओं की कमी का अध्ययन करना चाहिए। विमानतल से जल्दी पहुंचाए जाने वाले सामान की सेवाएं बढ़ें, जबकि रेल और सड़क के जरिए भंडारण व वितरण की सुविधाएं विकसित हों। बड़े कार्गो टर्मिनल पर निवेश से पहले माल की संभावित मात्रा, खर्च, पर्यावरण मंजूरी और निजी भागीदारी का आकलन जरूरी है। भोपाल को उद्योग और माल ढुलाई, दोनों के विकास की साझा योजना चाहिए।

क्षेत्रों में उत्पादन, सहायक उद्योग और रोजगार बढ़ाना भी जरूरी है।

जहांगीराबाद थाने में जल्ती के वाहनों में लगी आग, 5 कार और 1 स्कूटर जले



भोपाल। दोपहर मेट्रो

जहांगीराबाद थाना परिसर में खड़े जल्ती के वर्षों पुराने वाहनों में गुरुवार दोपहर को आग लग गई। हादसे में छह वाहन आग की चपेट में आ गए और जल गए। उधर भड़की आग को देखकर पुलिस ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल ने पहुंचकर तुरंत आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कुछ वाहन जल चुके थे। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। जहांगीराबाद थाना पुलिस ने मामले में आगजनी कायम की है।

जहांगीराबाद थाना प्रभारी हरिकिशन लोरिया ने बताया कि थाने के सामने परिसर में लंबे समय से जल्ती के कंडम वाहन खड़े हैं। गुरुवार दोपहर करीब 12:15 बजे ग्राउंड के पास खड़ी कारों में आग लग गई थी। हादसे में पांच कारें और एक स्कूटर जल गईं। पुलिस ने आग बुझाने का प्रयास किया और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया।

भोपाल में सेहत से बड़ा खिलवाड़ पनीर से लेकर दूध तक के सैंपल फेल 35 दुकानों पर केस दर्ज, भारी जुर्माना

भोपाल। दोपहर मेट्रो

राजधानी में लोगों की थाली तक पहुंच रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दूध, पनीर, क्रीम, घी से लेकर मिठाई और नमकीन तक जांच में कई खाद्य पदार्थ मानकों पर खरे नहीं उतरे। खाद्य सुरक्षा प्रशासन की प्रयोगशाला जांच में 35 प्रतिष्ठानों से जुड़े खाद्य नमूनों में अमानक और मिथ्या छाप के मामले सामने आए हैं। इनमें डेयरियों, होटल-रेस्टोरेंट, मिठाई दुकानों और किराना प्रतिष्ठानों के नाम शामिल हैं। दो दुकानों से लिए गए सोयाबीन तेल के नमूने प्रतिबंधित श्रेणी में पाए गए। अपर कलेक्टर न्यायालय में पिछले तीन महीनों के दौरान लंबित प्रकरणों की सुनवाई के बाद 6.50 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाते हुए प्रकरण दर्ज किया है।

पनीर पर बड़ा सवाल, दूध भी मानकों से बाहर

खाद्य सुरक्षा प्रशासन की कार्रवाई में पनीर के नमूने सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। बावड़िया कला की कृष्णा डेयरी, खजूरी सड़क के जीत ढाबा, चूना भट्टी स्थित होटल श्री रीजेंडेंसी, अयोध्या बायपास के शिव शंभू रेस्टोरेंट और एयरपोर्ट के होटल प्लाजा इन सहित कई प्रतिष्ठानों के पनीर के नमूने अमानक पाए गए। नीलबड़, कोलार, होशंगाबाद रोड, बैरसिया रोड और बागसेवानिया क्षेत्र के प्रतिष्ठान भी कार्रवाई के



दायरे में आए हैं। दूध की गुणवत्ता पर भी सवाल उठे हैं। कृष्णा दूध डेयरी, न्यू इंडियन डेयरी, राधे कृष्णा डेयरी, नेशनल डेयरी एंड स्वीट्स, महाकाल दूध डेयरी से संबंधित नमूनों में गड़बड़ी मिली। इसके अलावा नेशनल डेयरी की क्रीम और मनभावन किराना एंड जनरल स्टोर्स के घी का नमूना भी अमानक पाया गया है।

मिठाई और नमकीन भी शक के घेरे में

रानी स्वीट की मावा कतली, राजोरिया होटल की मावा बर्फी, अजय बेकरी एंड स्वीट्स की मावा बर्फी, तन्वी इंटरप्राइजेज के नमकीन खुरमा और एमआईएमएस कैटीन की पेटिस के नमूने मिथ्या छाप श्रेणी में पाए गए। गुप्ता पान मसाला स्टोर के मूंगफली दाने और कनक फैन्सी जनरल एंड किराना स्टोर की लाना सेव के नमूने भी जांच में सवालों के घेरे में आए।

पत्नी को कुल्हाड़ी से मारा पति ने खुद का रेता गला सुबह बच्चों ने देखे हालात

भोपाल। दोपहर मेट्रो

कोलार थाना क्षेत्र के अब्बास नगर में सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। पति ने सोते समय पत्नी के सिर पर कुल्हाड़ी से तीन वार किए और इसके बाद ब्लेड से खुद का गला रेत लिया। दोनों निजी अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने पति के विरुद्ध हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज किया है। प्रारंभिक जांच में वारदात की वजह पत्नी के चरित्र पर संदेह बताई जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दोनों में रात में कहासुनी हो गई थी। इसके बाद काफी देर तक बहस होती रही। बच्चों के सो जाने के बाद मामला और गर्मा गया। इस पर दोनों के बीच मारपीट भी हो गई थी। पत्नी जब रात को सो गई तो पति ने गुस्से में उस पर सोते समय कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।

गाय को बचाने में ब्रिज की दीवार तोड़कर 20 फीट नीचे गिरा ट्राला



भोपाल। दोपहर मेट्रो

गांधीनगर क्षेत्र में एयरपोर्ट रोड पर शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्राला अनियंत्रित होकर ब्रिज की सीमेंट की दीवार तोड़ते हुए करीब 20 फीट नीचे सर्विस लेन पर जा गिरा। हादसे में चालक, हेलपर और क्लीनर घायल हो गए। राहत की बात रही कि

उस समय सर्विस लेन पर कोई वाहन या राहगीर मौजूद नहीं था, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। टीआइ सुनील चतुर्वेदी ने बताया कि ट्राला गांधीनगर की ओर से परवलिा की ओर 10 लेन सड़क निर्माण के लिए लोडर माल खाली कर चांदुखेड़ी स्थित प्लांट लौट रहा था।

मेट्रो एंकर भोपाल में आज से सजेगा स्वदेशी मेला: हस्तशिल्प, घरेलू सामान और देशी उत्पाद भी रहेंगे

200 स्टॉलों पर सजेंगे हाथ से बने उत्पादों के रंग

भोपाल। दोपहर मेट्रो

भोपाल के एमवीएम ग्राउंड में शनिवार से स्वदेशी मेला सजेगा। इस मेले में देशभर के स्वदेशी उत्पादों, हस्तशिल्प, दैनिक उपयोग की वस्तुओं, स्थानीय उद्योगों और स्टार्टअप्स के 200 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। मेले में खरीदारी के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी।

स्वदेशी जागरण मंच और स्वर्णिम भारतवर्ष फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने वाले इस मेले से स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार मिलेगा। शुक्रवार को मेले की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। आयोजकों के मुताबिक, मेले में कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री का



अवसर मिलेगा। इसके जरिए युवाओं, महिलाओं और नए उद्यमियों को भी स्वरोजगार व उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित

किया जाएगा। हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों की प्रतियोगिताएं भी 12 दिन चलने वाले मेले में

प्रतिदिन सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। स्कूली बच्चों के कार्यक्रम के अलावा युवाओं को स्वदेशी विचार से जोड़ने के लिए नाटक और नृत्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। आयोजकों का कहना है कि इन गतिविधियों के जरिए नई पीढ़ी को भारतीय कला, संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने के साथ स्वदेशी उत्पादों के प्रति जागरूक किया जाएगा।

1991 में हुई थी स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना 22 नवंबर 1991 को नागपुर में हुई थी। मंच स्वदेशी विचार को आगे बढ़ाने के लिए देशभर में गतिविधियां आयोजित करता है। आयोजकों के अनुसार, वर्ष 1999 में दिल्ली से शुरू हुई स्वदेशी मेलों की श्रृंखला के तहत अब तक देशभर में 100 से अधिक आयोजन हो चुके हैं। भोपाल का मेला भी इसी क्रम में आयोजित किया जा रहा है।



इंदौर में सेमीकंडक्टर समिट-2026

प्रदेश को टेक्नोलॉजी हब बनाने पर जोर

इंदौर। मध्यप्रदेश में सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में मध्यप्रदेश सेमीकंडक्टर समिट-2026 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिट के माध्यम से प्रदेश को लगभग 5,800 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनसे 10 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक हजार से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी और जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान तथा स्वीडन के प्रतिनिधिमंडलों की मौजूदगी प्रदेश में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के प्रति बढ़ती वैश्विक रुचि को दर्शाती है।

दो दिन तक तकनीक और निवेश पर मंचन
दो दिवसीय समिट में सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़े विभिन्न विषयों पर आठ पैनल चर्चाएं, पांच राउंडटेबल बैठकें और छह की-नोट उद्घोषण आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही मध्यप्रदेश सेमीकंडक्टर नीति-2026 पर हितधारकों के साथ चर्चा और एमपी सेमीकॉन स्टार्टअप चैलेंज भी कार्यक्रम का हिस्सा हैं।

मप्र में प्राचार्यों के हजारों पद खाली

2 महीने बाद भी 196 पदोन्नत व्याख्याताओं की पोस्टिंग नहीं

रिटायरमेंट के करीब पहुंचे शिक्षकों को नई पदस्थापना का इंतजार



पोस्टिंग नहीं होने से पदोन्नति के लाभ से वंचित

कौशल ने कहा कि प्राचार्यों के पद रिक्त रहने से विद्यालयों की प्रशासनिक निगरानी, शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन तथा संस्थागत व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका बनी हुई है। वहीं, पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी पदस्थापना के आदेश जारी नहीं होने से शिक्षकों को पदोन्नति का वास्तविक लाभ समय पर नहीं मिल पा रहा है। सेवानिवृत्ति के करीब पहुंचे शिक्षकों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग से मांग की कि पदोन्नत व्याख्याताओं की पदस्थापना के आदेश तत्काल जारी किए जाएं तथा सेवानिवृत्ति के करीब पहुंचे शिक्षकों के मामलों को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही, प्राचार्यों के रिक्त पदों को भरने की लंबित प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए, ताकि विद्यालयों में प्रशासनिक एवं शैक्षणिक

जाने पर भी पदस्थापना के आदेश जारी नहीं होना समझ से परे है। विभागीय प्रक्रिया में हो रहे विलंब के कारण पदोन्नत शिक्षक अपने नए पद का दायित्व संभालने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

सिंहस्थ 2028 की तैयारी: 60 दिन में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान

15 जिलों में 16 हजार हेक्टेयर में होगी सब्जी-फूलों की खेती, 20 हजार किसानों को जोड़ने का है लक्ष्य

उज्जैन, दोपहर मेट्रो

सिंहस्थ 2028 में करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने खाद्य सामग्री और पूजन में इस्तेमाल होने वाले फूलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इतने बड़े आयोजन के दौरान सब्जियों और फूलों की मांग में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए उद्यानिकी विभाग ने दो साल का रोडमैप तैयार किया है। इसके तहत प्रदेश के 15 जिलों में 16 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जियों और फूलों का अतिरिक्त उत्पादन करने की योजना है। इस पहल के जरिए करीब 20 हजार किसानों को जोड़कर मांग के अनुरूप खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।

सिंहस्थ के 60 दिनों में करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। इस हिसाब से प्रतिदिन औसतन 66.67 लाख श्रद्धालुओं की आवाजाही हो सकती है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लिए भोजन और धार्मिक गतिविधियों की व्यवस्था करना चुनौतीपूर्ण होगा। हालांकि, सब्जियों की वास्तविक मांग श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन व्यवस्था और खपत के स्वरूप पर निर्भर करेगी। इसी को देखते हुए उत्पादन और आपूर्ति को पहले से योजना बनाने पर जोर दिया जा रहा है। उद्यानिकी विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, 16 हजार हेक्टेयर में अतिरिक्त उत्पादन विकसित किया जाएगा। इसमें 8 हजार हेक्टेयर में सब्जियों और 8 हजार हेक्टेयर में फूलों की खेती को बढ़ावा देने की योजना है। इसके लिए करीब 20 हजार किसानों को चिह्नित किया जा रहा है। योजना के तहत क्लस्टर आधारित मॉडल अपनाया जाएगा। इसमें एक क्षेत्र के किसान मांग के अनुसार निर्धारित फसलों का योजनाबद्ध तरीके से उत्पादन करेंगे।



15 जिलों से उज्जैन तक पहुंचेगी उपज

सिंहस्थ के दौरान सब्जियों और फूलों की पूरी जरूरत केवल उज्जैन जिले से पूरी करना संभव नहीं होगा। इसलिए उद्यानिकी विभाग ने 15 जिलों को जोड़कर उत्पादन और आपूर्ति का नेटवर्क तैयार करने की योजना बनाई है। इसमें किसानों से उपज एकत्र करने, ग्रेडिंग, पैकिंग और परिवहन तक की व्यवस्था को व्यवस्थित किया जाएगा। इस नेटवर्क से अलग-अलग जिलों में संभावित उत्पादन की जानकारी पहले से उपलब्ध रहेगी। किसी क्षेत्र में उत्पादन कम होने पर दूसरे जिलों से आपूर्ति बढ़ाने की गुंजाइश भी रहेगी। इससे किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम करने और आयोजन के दौरान निरमित उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

सात जिलों में सब्जियों के उत्पादन पर फोकस

सब्जियों के अतिरिक्त उत्पादन के लिए उज्जैन संभाग के उज्जैन, आगर-मालवा, शाजापुर, देवास, रतलाम, नीमच और मंदसौर जिलों को शामिल करने का प्रस्ताव है। इन जिलों में दो साल के भीतर 8 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में हाइब्रिड सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने की योजना है। किसानों को आधुनिक खेती की तकनीक, फसल चयन और उत्पादन प्रबंधन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

आठ जिलों में फूलों की खेती

सिंहस्थ में मंदिरों, अखाड़ों, आश्रमों, धार्मिक शिविरों और श्रद्धालुओं की पूजा के लिए फूलों की मांग भी बढ़ेगी। इसके लिए उज्जैन, इंदौर, देवास, आगर-मालवा, खंडवा, छतरपुर, मेहर और दतिया में 8 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती विकसित करने का प्रस्ताव है। उज्जैन में गेंदा उत्पादन को विशेष रूप से बढ़ावा देने की योजना है। इसके तहत करीब 4,200 हेक्टेयर क्षेत्र में गेंदा उत्पादन के लिए 25 क्लस्टर और 240 गांवों को जोड़ने का प्रस्ताव है। वहीं, गुलाब की खेती का रकबा बढ़ाकर 250 हेक्टेयर से अधिक करने की तैयारी है। आधुनिक तकनीक और किसानों के प्रशिक्षण के लिए करीब 19 एकड़ में सेंटर ऑफ एक्सपर्टिसेस फॉर फ्लोरीकल्चर विकसित करने की योजना भी बनाई गई है।

खेत से मेला क्षेत्र तक उपज पहुंचाना होगी असली परीक्षा

उत्पादन बढ़ाने के साथ सबसे बड़ी चुनौती सब्जियों को समय पर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की होगी। जल्दी खराब होने वाली सब्जियों के लिए संग्रहण केंद्र, ग्रेडिंग, पैकिंग और जरूरत के अनुसार कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था जरूरी होगी। इसके अलावा तेज परिवहन और मांग-आपूर्ति का डिजिटल रिकॉर्ड भी महत्वपूर्ण रहेगा। यदि उत्पादन, भंडारण और परिवहन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होता है, तो सिंहस्थ के दौरान सब्जियों और फूलों की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

जीतू पटवारी ने चार संभागों की टटोली नब्ज

कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की कवायद तेज

भोपाल, दोपहर मेट्रो

मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय, भोपाल में चार संभागों की संगठनात्मक समीक्षा बैठक ली। बैठक में जबलपुर, सागर, नर्मदापुरम और इंदौर संभाग के संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा करते हुए जिला, विधानसभा और बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया गया। बैठक में संगठन महामंत्री संजय कामले, प्रदेश महासचिव गौरव रघुवंशी सहित संबंधित संभागों के जिला अध्यक्ष,

संगठनात्मक समन्वय और जनसंपर्क बढ़ाने पर जोर

समीक्षा बैठक में पार्टी की रणनीति को जमीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से लागू करने और संगठन के विभिन्न स्तरों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया गया। जिला एवं विधानसभा स्तर पर चल रही गतिविधियों की समीक्षा के साथ पदाधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने तथा निर्धारित कार्ययोजना के अनुरूप कार्यों में तेजी लाने पर चर्चा हुई।

जिला प्रभारी, विधानसभा प्रभारी और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे।

अप्रैल-मई 2027 में हो सकते हैं पंचायत चुनाव

ग्रामसभा के अधिकार समितियों को देगी सरकार निगमों की तरह पंचायतें भी लगा सकेंगी टैक्स

भोपाल, दोपहर मेट्रो

मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव अप्रैल-मई 2027 में हो सकते हैं। डॉ. मोहन यादव सरकार प्रदेश की करीब 23 हजार पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने से एक-दो महीने पहले चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। चुनाव से पहले पंचायत राज व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी भी है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा- ग्राम सभा के अधिकार पंचायत समितियों को दिए जाएंगे। सरकार नवंबर तक नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। इसके अलावा पंचायतों को नगरपालिका की तरह टैक्स लगाने का अधिकार देने की दिशा में भी



काम हो रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने बालाघाट जिले के वारासिवनी जनपद की ग्राम पंचायत गरं में सरपंच सम्मेलन के दौरान ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि आगामी पंचायत चुनाव कार्यक्रम पूरा होने से एक या दो महीने पहले कराए जाएंगे, ताकि नई पंचायतों को समय पर कार्यभार सौंपने की प्रक्रिया पूरी हो सके।

नवंबर तक लागू कर सकती है सरकार

सरकार नवंबर तक यह बदलाव लागू करना चाहती है। ग्राम सभा गांव के विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करने के साथ कई फैसलों में अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में उसके अधिकार पंचायत समितियों को देने का प्रस्ताव पंचायत राज व्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा। सरकार पंचायतों को नगरपालिका की तरह टैक्स लगाने का अधिकार देने की दिशा में काम कर रही है।



बंजारा डैम, किला और वार्ड-10 में बनेंगे एसटीपी

18 करोड़ से संवरेगी शीप नदी की सूरत, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से रुकेगा गंदे नालों का पानी

श्योपुर, दोपहर मेट्रो

गंदे नालों की गंदगी खले जाने से दुर्दशा का शिकार हो रही श्योपुर की जीवनदायिनी शीप नदी की सूरत 18 करोड़ रुपये की लागत से संवारी जाएगी। नदी को गंदे नालों और कचरे के दंश से मुक्ति दिलाने के लिए शहर के तीन अलग-अलग स्थानों पर तीन सीवर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे। प्लांटों की मदद से नालों के दूषित पानी को उपचारित करने के बाद ही नदी में प्रवाहित किया जाएगा। परियोजना के लिए टेंडर जारी हो चुके हैं और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है।

नदी पर लगातार बढ़ता जा रहा है अपशिष्ट का दबाव- यहां बता दें कि, श्योपुर शहर में आबादी बढ़ने के साथ घरेलू गंदे पानी और नालों से आने वाले अपशिष्ट का दबाव नदी पर लगातार बढ़ता जा रहा है। नतीजतन, स्वच्छ जलधारा के बजाय इसके कई हिस्से गंदगी से प्रभावित होने लगे हैं। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए अब नगर पालिका श्योपुर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित करने की योजना पर काम आगे बढ़ाया जा रहा है।

नालों का पानी सीधी नदी में नहीं पहुंचेगा वाल्ट फिल्टर करके डाला जाएगा

वर्तमान समय में शहर के विभिन्न हिस्सों से निकलने वाला दूषित पानी नालों के जरिए शीप नदी तक पहुंच रहा है। इससे जल की गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ नदी के प्राकृतिक स्वरूप पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। प्रस्तावित व्यवस्था में गंदे पानी को उपचारित करने के लिए संबंधित प्लांट तक पहुंचाया जाएगा। वहां आवश्यक प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही पानी नदी में छोड़ा जाएगा। इससे अनुपचारित अपशिष्ट का प्रवाह रोकने और प्रदूषण का दबाव कम करने में मदद मिलेगी।

तीन स्थानों पर बनेंगे प्लांट

परियोजना के तहत शहर में तीन स्थानों पर प्लांट बनाए जाएंगे। इनमें बंजारा डैम, किले के निचले इलाके और वार्ड क्रमांक 10 को शामिल किया गया है। इन इकाइयों के निर्माण पर कुल 18 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की योजना है। नगर पालिका ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। जल्द निर्माण शुरू होने की संभावना है।

मेट्रो एंकर

तेंदुपत्ता संग्राहकों के बच्चों की शिक्षा को सहाय दे रही एकलव्य शिक्षा छात्रवृत्ति योजना

2,216 विद्यार्थियों को मिली 2.77 करोड़ की आर्थिक मदद

भोपाल, दोपहर मेट्रो

मध्यप्रदेश में तेंदूपत्ता संग्रहण से जुड़े जनजातीय एवं वनांचल क्षेत्रों के परिवारों के बच्चों को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार एकलव्य शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता दे रही है। वर्ष 2025-26 में योजना के तहत 2,216 विद्यार्थियों को कुल 2 करोड़ 77 लाख 16 हजार रुपये की छात्रवृत्ति वितरित की गई। अब वर्ष 2026-27 में इसके लिए 5 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे अधिक पात्र विद्यार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

छात्रवृत्ति बजट में करीब 80 प्रतिशत की बढ़ोतरी- योजना के तहत पिछले वर्ष 1,180 छात्र और



1,036 छात्राएं लाभान्वित हुईं। छात्राओं की भागीदारी कुल लाभार्थियों में लगभग 47 प्रतिशत रही। वर्ष 2026-27 के लिए 5 करोड़ रुपये का लक्ष्य पिछले वर्ष वितरित राशि से करीब 80 प्रतिशत अधिक है। बजट में इस बढ़ोतरी का उद्देश्य वन आधारित आजीविका से जुड़े परिवारों

के बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना है।

कक्षा 9वीं से उच्च शिक्षा तक आर्थिक मदद- एकलव्य शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं तक तथा महाविद्यालयों में पढ़ने वाले पात्र विद्यार्थियों को निर्धारित नियमों के अनुसार छात्रवृत्ति दी जाती

है। शिक्षण सत्र 2022-23 से लागू दरों के अनुसार कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को अधिकतम 15 हजार रुपये, कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को 18 हजार रुपये, गैर-तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 25 हजार रुपये और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अधिकतम 60 हजार रुपये तक

सहायता का प्रावधान है। पात्रता के लिए पिछले पांच वर्षों में कम से कम तीन वर्षों तक प्रत्येक वर्ष एक मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण की शर्त सहित निर्धारित शैक्षणिक मानदंड लागू हैं। वास्तविक छात्रवृत्ति राशि पात्रता और योजना के नियमों के आधार पर निर्धारित होती है।

बीमारी जब किसी घर का दरवाजा खटखटाती है, तो परिवार की पहली चिंता मरीज को बचाने की होती है। लेकिन कैन्सर जैसी गंभीर बीमारी में जीवन बचाने की जद्दोजहद के साथ आर्थिक अस्तित्व का संघर्ष भी शुरू हो जाता है। जमा पूंजी खर्च होती है, कर्ज लेना पड़ता है और वर्षों की मेहनत इलाज के बिलों में सिमट जाती है। सवाल यह है कि क्या स्वस्थ जीवन पाने का अधिकार इतना महंगा होना चाहिए कि मरीज बीमारी से लड़ते-लड़ते आर्थिक रूप से भी टूट जाए? सुप्रीम कोर्ट में दवाओं की कीमतों पर चल रही सुनवाई ने इसी गंभीर सवाल को सामने रखा है।

संयुक्त राष्ट्र दिवस पर विशेष

बदलती दुनिया और 81 साल बाद भी अधूरी संयुक्त राष्ट्र की शांति-प्रतिज्ञा

योगेश कुमार गोयल
स्तंभकार

दुनिया के 50 देशों ने वर्ष 1945 में मिलकर संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर कर संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया था, जिसके बाद से प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। दरअसल द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अधिक समतापूर्ण और न्यायोचित बनाने के लिए एक नए संगठन की स्थापना का विचार उभरा था, जो पांच राष्ट्रमंडल सदस्यों तथा आठ यूरोपीय निर्वासित सरकारों द्वारा 12 जून 1941 को लंदन में हस्ताक्षरित अंतर-मैत्री उद्घोषणा में पहली बार सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त हुआ था। उस उद्घोषणा के अंतर्गत एक स्वतंत्र विश्व के निर्माण हेतु कार्य करने का आह्वान किया गया था, जिसमें लोग शांति और सुरक्षा के साथ भयमुक्त वातावरण में रह सकें तथा निजीकरण एवं आर्थिक सहयोग के मार्ग की खोज कर सकें। उसके बाद 1944 में सोवियत संघ, अमेरिका, चीन तथा ब्रिटेन के प्रतिनिधियों द्वारा वाशिंगटन के डम्बर्टन ओक्स एस्टेट में कई बैठकों के आयोजन के बाद एक शांतिरक्षक वैश्विक संस्था बनाने की रूपरेखा तैयार की गई, जिसके आधार पर 50 देशों के प्रतिनिधियों के बीच 1945 में बातचीत हुई और 26 जून 1945 को सभी 50 देशों द्वारा चार्टर पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद यह चार्टर 24 अक्टूबर 1945 से प्रभावी हो गया। तभी से प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को ‘संयुक्त राष्ट्र दिवस’ मनाया जाने लगा।

अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ को इतनी शक्तियां प्रदान की गई कि वह अपने सदस्य देशों की सेनाओं को विश्व शांति के लिए कहीं भी तैनात कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से ही दुनिया के अनेक देश इसके साथ जुड़ते गए और 50 सदस्यों के साथ शुरू हुए इस वैश्विक संघ के सदस्य देशों की संख्या अब 193 हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र की संरचना में सुरक्षा परिषद वाले सबसे शक्तिशाली देश थे अमेरिका, फ्रांस, रूस तथा यूनाइटेड किंगडम, जिनकी द्वितीय विश्वयुद्ध में अहम भूमिका थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्यों में युद्ध रोकना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, सभी देशों के बीच मित्रवत संबंध कायम करना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को निभाने की प्रक्रिया जुटाना, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, निधन तथा भूखे लोगों की सहायता करना, उनका जीवन स्तर सुधारना, बीमारियों से लड़ना इत्यादि शामिल हैं और इन उद्देश्यों को निभाने के लिए 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा प्रमाणित की गई। हालांकि विडम्बना है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के इन 81 वर्षों में यह वैश्विक संस्था अब धीरे-धीरे अपनी प्रासंगिकता खोने लगी है। दरअसल बीते 81 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थव्यवस्था, हथियार, मीडिया, समाज, मुद्रा तथा समाज से संबंधित तमाम नीतियां इसके पांच स्थायी सदस्य देशों ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, रूस तथा फ्रांस के राष्ट्रीय हितों के अनुरूप ही निर्धारित की जाती रही हैं, जिस कारण ऐसी नीतियों का खामियाजा भारत के अलावा जापान, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, इजरायल, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे कई अन्य देशों को भुगतना पड़ा है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थायी सदस्यता के लिए तमाम मानदंडों को पूरा करने के बाद भी दशकों से सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने के लिए प्रयासरत हैं।



संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के आठ दशकों में विश्व के सामरिक और आर्थिक समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं लेकिन इतना लंबा समय बीत जाने और तमाम वैश्विक समीकरण पूर्ण रूप से बदल जाने के बावजूद वीटो अधिकार वाले पांचों स्थायी सदस्यों में से कोई भी अपने वीटो अधिकार और स्थायी सीट को छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर संयुक्त राष्ट्र में आम सहमति है लेकिन चीन को खासकर एशिया से वीटो अधिकार वाले सदस्यों की संख्या बढ़ाना किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है, जहां स्थायी सदस्यता के दोनों दावेदारों (भारत और जापान) पर वह विभिन्न कारणों से संदेह करता है। भारत ने जिस चीन को मान्यता देने में पहल की थी और सुरक्षा परिषद में उसकी स्थायी सीट को सिद्धांत के तौर पर लेने से मना कर दिया था, आज वही चीन भारत की स्थायी सदस्यता के मार्ग में रोड़े अटका रहा है। भारत चीन के वीटो पावर के कारण ही सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बन पा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित किए जाने वाले प्रस्ताव बाध्यकारी प्रकृति के नहीं होते। आश्चर्य की बात है कि महासभा में 193 सदस्य देशों द्वारा पारित किए जाने वाले प्रस्ताव भी सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों की सहमति पर ही निर्भर करते हैं। इसीलिए अनेक देशों द्वारा इसमें सुधार किए जाने की मांग बीते कई वर्षों से निरंतर की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी की वकालत करते हुए कह चुके हैं कि नई ताकतों को केन्द्रीय भूमिका में लाए बिना दुनिया की यह सबसे बड़ी पंचायत स्वयं से की जाने वाली अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाएगी। दुनिया के कई देश बार-बार कहते रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र का ढांचा अब पुराना पड़ चुका है और इसकी स्थापना के समय जो परिस्थितियां थी, वे अब बहुत पुरानी हो चुकी हैं। इसलिए यदि यह वैश्विक संस्था अपने भीतर समयानुकूल सुधार नहीं लाती है तो कालांतर में यह महत्वहीन होती चली जाएगी।

रूस-यूक्रेन युद्ध हो या इजरायल-फिलस्तीन अथवा अमेरिका-ईरान युद्ध, इन संघर्षों में दोनों ही पक्षों के हजारों बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, हजारों परिवार उजड़ चुके हैं, लाखों की आबादी पलायन की त्रासदी से जूझ रही है, शहर के शहर मलबे में तब्दील हो रहे हैं लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ इन संघर्षों को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सका है। इसीलिए दुनिया में जगह-जगह युद्ध टालने के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से ठोस योजनाओं पर अमल किए जाने की जरूरत महसूस होती रही है क्योंकि इस वैश्विक संस्था का गठन ही दुनिया में अमन-चैन कायम रखने के उद्देश्य के साथ किया गया था लेकिन चिंता की बात है कि इन युद्धों में उसकी निष्क्रियता समूची मानव सभ्यता पर भारी पड़ रही है। भीषण होते इन युद्धों के कारण दुनिया अब दो धड़ों में बंटती जा रही है और संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश सदस्य देश भी अब केवल बयान जारी करने से आगे नहीं बढ़ रहे। बहरहाल, यदि अभी भी संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती है तो यह संस्था अपने वाले समय में अपना महत्व खो देगी। सही मायनों में दुनिया की इस सबसे बड़ी पंचायत को अब गंभीर आत्ममंथन की जरूरत के साथ पर्याप्त सुधारों की सख्त दरकार है।

—यह लेखक के अपने विचार हैं।

मुनाफे का बाजार

चिकित्सा सामग्रियों की कीमतें खरीद लागत से क्रमशः 52 और 67 गुना तक जिसमें मरीज अक्सर कीमतों की पड़ताल करने की स्थिति में नहीं होता। अस्पताल में भर्ती मरीज दवाओं, जांच और चिकित्सा सामग्री के लिए काफी हद तक अस्पताल पर निर्भर रहता है। ऐसे में पारदर्शिता कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं, बल्कि उसका बुनियादी अधिकार है। केवल दवाओं के ट्रेड मार्जिन पर सीमा लगाना पर्याप्त नहीं होगा। अस्पताल कमरे का किराया, जांच शुल्क या इलाज के

महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ते अपराध, राष्ट्रीय राजधानी सबसे असुरक्षित

मनोज कुमार अग्रवाल
स्तंभकार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों और वारदातों पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते बलात्कार और यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय और एमसीडी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि दक्षिण दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में बंदूक की नोक पर पुलिसकर्मी बनकर 17 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना में सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इससे पहले दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई।

इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ग्रेटर नोएडा से दिल्ली आ रही एक चलती स्लीपर बस के भीतर एक और नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न किया गया। एक हालिया अध्ययन के अनुसार, दिल्ली में सड़क, मेट्रो और बसों में महिलाओं से छेड़खानी और यौन उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे महिलाएं डर के मारे अपने सफर का समय और मार्ग बदलने को मजबूर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल वारदात होने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करना पर्याप्त नहीं है; पुलिस का मुख्य काम अपराध होने से रोकना होना चाहिए। कोर्ट ने रात के समय महिलाओं की सुरक्षा, प्रमुख स्थानों पर पर्याप्त रोशनी, सीसीटीवी निगरानी और पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। एनसीआरबी के हालिया डेटा के मुताबिक, देश के सभी महानगरों की तुलना में दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और बलात्कार के मामले सबसे अधिक दर्ज किए जा रहे हैं, जिसके कारण यह लगातार असुरक्षित शहरों की सूची में ऊपर बना हुआ है। हाल ही में दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर विभिन्न महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं ने महिलाओं और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित यौन हिंसा एवं उत्पीड़न के मामलों में जवाबदेही और सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किए हैंदेश की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के आस-पास के क्षेत्र जिसे एन.सी.आर. भी कहा जाता है, में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उभर कर बार-बार सामने आ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस क्षेत्र में विगत दिवस नाबालिग लड़कियों और महिलाओं के साथ हुए अपराधों से संबंधित समाचारों का स्वयं ही गम्भीर संज्ञान लेते हुए कड़ी टिप्पणियां की थीं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी के आस-पास घटित होती ऐसी घटनाओं का नाला लागू करने वाली एजेंसियों की विफलता को दर्शाती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से इस संबंध में दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म, दिल्ली के स्वरूप नगर क्षेत्र में कथित सामूहिक दुष्कर्म के उपरांत नाबालिग लड़की की हत्या और चलती स्लीपर बस में एक और नाबालिग लड़की के कथित शारीरिक शोषण आदि से संबंधित समाचारों का संज्ञान लिया था। इस मामले के संबंध में जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद की पीठ ने सुनवाई करते हुए टिप्पणी की थी कि घटित उपरोक्त



घटनाओं की तुलना 2012 में दिल्ली में घटित हुए निर्भया कांड से की जा सकती है। उन्होंने कहा कि बड़ा सवाल यह है कि निर्भया कांड के बाद अब तक कि कानून व्यवस्था में कोई सुधार हुआ है या नहीं? उन्होंने यह भी कहा कि इन घटनाओं से एक बार फिर कानून लागू करने वाली एजेंसियों और सिविल प्रशासन की विफलता सामने आई है और सिस्टम लोगों को मूलभूत सुरक्षा मुहैया करने में विफल होता दिखाई दे रहा है। माननीय न्यायाधीशों ने यह भी कहा था कि दिल्ली के पार्कों, सड़कों, बसों, मेट्रो स्टेशनों, भूमिगत रास्तों और पैदल चलने वाले स्थानों विशेष रूप से जिन क्षेत्रों में रात को रोशनी कम होती है, को जोरिखम वाले क्षेत्र बनने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। निःसंदेह सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त न्यायाधीशों द्वारा दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्र में महिलाओं की असुरक्षा संबंधी की गई टिप्पणियां बेहद गम्भीर थीं और इनका न केवल दिल्ली के प्रशासन को, अपितु केन्द्र सरकार और देश के अन्य विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासन को भी गम्भीरता से संज्ञान लेना चाहिए। इस संबंध में दीर्घ विचार-विमर्श होना चाहिए कि

सरकारों के ज्यादातर यत्नों और विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कड़े कानून बनाने के बावजूद देश के अधिकतर भागों में आज भी महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं हैं? असामाजिक तत्वों के मन में सरकार और संबंधित प्रशासन का कोई डर क्यों नहीं है? केन्द्र से लेकर राज्य स्तर तक देश में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने के लिए गम्भीर चर्चा करके कोई

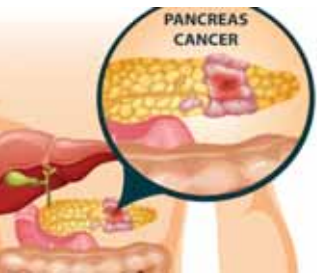
उचित कार्य योजना बनाने की जरूरत फिर महसूस हो रही है। सरकारों को इस संबंध में यह भी देखना चाहिए, कि अमन-कानून लागू करने वाली एजेंसियां इस संबंध में क्यों विफल रहती हैं? उनकी कार्यशैली में और किस प्रकार के सुधार किए जा सकते हैं? इसके साथ-साथ सरकारों को यह भी देखने की जरूरत है कि समाज में ऐसे तत्व क्यों बढ़-फूल रहे हैं, जोकि महिलाओं का मान-सम्मान करने के स्थान पर उनका शारीरिक शोषण करने को तैयार रहते हैं। उनकी ऐसी मानसिकता कहां से बनती है? क्या इसका कारण सोशल मीडिया पर मौजूद अश्लील सामग्री तो नहीं है? क्या इसका कारण मनोरंजन चैनलों पर लगातार चलते अश्लील किस्स के धारावाहिक तो नहीं हैं या क्या इसका कारण यह तो नहीं है कि हमारा समाज पारिवारिक नैतिक मूल्यों से वंचित होता जा रहा है। परिवारों के भीतर अभिभावकों द्वारा जो निरंतर अपने बच्चों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती थी, उसमें कोई कमी तो नहीं आ गई। ये सभी ज्वलंत सवाल हैं, जिनके संबंध में गम्भीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि यह मामला सिर्फ अमन-कानून का ही नहीं, अपितु हमारे समाज के भीतर नैतिक मूल्यों के पक्ष से आ रही बड़ी गिरावट का भी है।

अदालत ने सवेदनशील इलाकों मेंसीसीटीवी कैमरों की निगरानी, पर्याप्त रोशनी (स्ट्रीट लाइट्स) और पुलिस पेट्रोलिंग को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय गृह मंत्रालय और एमसीडी से सुरक्षा उपायों पर चार हफ्ते के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। निःसंदेह महिलाओं के बड़े भाग ने शिक्षा प्राप्त करके प्रत्येक क्षेत्र में पहले से अधिक योगदान डाला है, परन्तु उनकी सुरक्षा के लिए देश में अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत है।

—यह लेखक के अपने विचार हैं।

हेल्थ अपडेट

शरीर को स्वस्थ रखने में पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय की अहम भूमिका होती है। पेट के ऊपरी हिस्से में, पेट के पीछेस्थित यह अंग भोजन पचाने के साथ ब्लड में शुगर का स्तर नियंत्रित रखने में भी मदद करता है। इसकी कार्यक्षमता प्रभावित होने पर पाचन संबंधी समस्याएं, अग्न्याशय में सूजन और कुछ स्थितियों में मधुमेह का खतरा बढ़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार संतुलित खानपान, नियमित व्यायाम, स्वस्थ वजन और धूम्रपान से दूरी बनाकर अग्न्याशय को स्वस्थ रखने में मदद मिल सकती है।



मदद करते हैं। इससे शरीर पोषक तत्वों को आसानी से अवशोषित कर पाता है। यह बाइकार्बोनेट भी बनाता है, जो छोटी

अग्न्याशय के दो प्रमुख कार्य हैं। पहला, यह ऐसे पाचक एंजाइम बनाता है जो भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को छोटे घटकों में तोड़ने में

आंत में पहुंचने वाले पेट के अम्ल को निष्क्रिय करने में मदद करता है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हार्मोन बनाना है। अग्न्याशय से निकलने वाला इंसुलिन रक्त में बढ़ी हुई शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करता है। वहीं, ग्लूकागॉन हार्मोन रक्त में शर्करा का स्तर कम होने पर उसे बढ़ाने में भूमिका निभाता है। अग्न्याशय को स्वस्थ रखने के लिए भोजन में सब्जियां, फल, साबुत अनाज और उचित मात्रा में प्रोटीन शामिल करें। अधिक तली-भुनी चीजों, अत्यधिक वसा वाले भोजन और जल्द से ज्यादा मीठे पदार्थों का सेवन सीमित रखें। नियमित शारीरिक गतिविधि और वजन पर नियंत्रण भी महत्वपूर्ण है। धूम्रपान से बचें, क्योंकि इसका संबंध अग्न्याशय में सूजन और

अन्य बीमारियों के बढ़ते जोखिम से है। शराब का अधिक सेवन भी अग्न्याशय को चुकसान पहुंचा सकता है। जिन्हें पहले अग्न्याशय में सूजन की समस्या रही है, उन्हें शराब से पूरी तरह दूर रहने की सलाह दी जाती है।

पेट के ऊपरी हिस्से में तेज या लगातार दर्द, पीठ तक फैलता दर्द, उल्टी, बुखार अथवा बिना कारण वजन कम होने जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तेज दर्द और लगातार उल्टी होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लें। मधुमेह, पित्त की पथरी या रक्त में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने की समस्या वाले लोगों को भी चिकित्सकीय सलाह के अनुसार नियमित देखभाल करनी चाहिए।

निशाना

वो मुसाफिर राह से भटक नहीं...



प्रदीप कश्यप

खुल्लू नफरत जो कभी करता नहीं। प्रेम का वो पाठ पढ़ पाया नहीं। दे रहा है जो बढ़ावा झूठ को। वे किसी से बात सच कहता नहीं। सुख लुटाए खूब जिस इंसान ने। अपना दुख उसने तो बतलाया नहीं। दीप जब हमने जला कर रख दिए। तब अंधेरा रात का छया नहीं। जिसको मंजिल का पता मालूम था। वो मुसाफिर राह से भटका नहीं। रोये हम जिसको बहुत कर के विदा। उस ने मुड़ कर के जरा देखा नहीं। जिंदगी जो शान से कश्यप जिया। वे किसी के पाँवों में झुकता नहीं।

वायरल कंटेंट

दुबई की चमक-दमक के पीछे छिपा संघर्ष भारतीय पंडित ने बताई कमाई की कहानी

दुबई का नाम सुनते ही आलीशान इमारतें, महंगी गाड़ियां और शानदार जीवनशैली की तस्वीर सामने आने लगती है। बेहतर कमाई की उम्मीद में दुनिया भर से लोग यहां पहुंचते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की जिंदगी वैसी नहीं होती, जैसी बाहर से दिखाई देती है। मध्य

प्रदेश के जबलपुर निवासी शास्त्री नीरज पंडित की कहानी भी इसी हकीकत को सामने लाती है। दुबई में पूजा-पाठ करकर आजीविका चलाने वाले नीरज ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बताया कि एक समय ऐसा भी था, जब सुबह का भोजन मिलने के बाद शाम को खाने का इंतजाम कैसे होगा, इसकी चिंता सताने लगती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक, सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में नीरज पंडित से दुबई में उनकी कमाई के बारे में पूछा गया। उन्होंने बताया कि उनकी कोई निश्चित मासिक तनखाह नहीं है। आमनी इस बात पर निर्भर करती है कि कितनी पूजा का काम मिलता है और किस तरह का धार्मिक आयोजन करना है। नीरज के मुताबिक, कभी एक पूजा कराने के लिए 500 दररम

यानी लगभग 12,800 रुपये मिल जाते हैं, तो कभी केवल 200 दरिहम यानी करीब 5,000 रुपये ही मिलते हैं। इस तरह हर महीने होने वाली कुल कमाई का अनुमान पहले से लगाना आसान नहीं है। पूजा की संख्या और काम मिलने की नियमितता उनकी आमदनी को सीधे



प्रभावित करती है। विदेश में नई जिंदगी शुरू करना आसान नहीं होता। अपना घर और परिवार छोड़कर दूसरे देश पहुंचने वाले व्यक्ति को रहने, खाने और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए नए सिरे से व्यवस्था करनी पड़ती है। नीरज ने अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया कि उस समय आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि सुबह खाना मिल जाने के बाद शाम के भोजन की चिंता शुरू हो जाती थी। यह संघर्ष केवल पैसों तक सीमित नहीं था। दूसरे देश में अपने लिए जगह बनाना, काम तलाशना और जीवन को व्यवस्थित करना भी बड़ी चुनौती थी। उनकी कहानी बताती है कि विदेश में टिकने और अपनी पहचान बनाने के लिए कई लोगों को कठिन दौर से गुजरना पड़ता है।

कंज्यूमर अपडेट

फाइबर या केबल ब्रॉडबैंड, घर के लिए कौन सा इंटरनेट कनेक्शन रहेगा बेहतर...

घर में वाई-फाई कनेक्शन लगावाते समय केवल इंटरनेट की कीमत और डाउनलोड स्पीड देखना पर्याप्त नहीं है। यह भी समझना जरूरी है कि कनेक्शन किस तकनीक पर काम करता है, अपलोड की गति कितनी है और एक साथ कई उपकरण चलाने पर इंटरनेट कैसा प्रदर्शन करता है। आमतौर पर फाइबर और केबल ब्रॉडबैंड के विकल्प मिलते हैं। फाइबर ब्रॉडबैंड में कांच के बेहद महीन रेशों से बने तारों के जरिए प्रकाश संकेतों की मदद से डेटा पहुंचता है। इसके कारण यह तकनीक बहुत तेज गति और अधिक क्षमता वाला इंटरनेट उपलब्ध करा सकती है। वहीं, पारंपरिक केबल ब्रॉडबैंड में कोएरिसिवल केबल का इस्तेमाल होता है, जिसमें तांबे के जरिए विद्युत संकेतों से डेटा पहुंचता है। ध्यान रखें कि इंटरनेट की वास्तविक गुणवत्ता केवल तकनीक पर निर्भर नहीं करती। सेवा प्रदाता के नेटवर्क, आपके क्षेत्र में उपलब्ध क्षमता और घर के राउटर की स्थिति का भी असर पड़ता है। फाइबर कनेक्शन का बड़ा फायदा इसकी अपलोड और डाउनलोड गति है। कई फाइबर योजनाओं में दोनों की गति



समान होती है। इसे समान अपलोड-डाउनलोड गति कहा जाता है। यह सुविधा वीडियो कॉलिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, बड़ी फाइलें भेजने और घर से काम करने वालों के लिए उपयोगी है। केबल ब्रॉडबैंड में डाउनलोड गति अच्छी मिल सकती है, लेकिन अपलोड गति अक्सर डाउनलोड के मुकाबले कम होती है। इसके अलावा, साझा नेटवर्क पर अधिक लोगों के इंटरनेट इस्तेमाल करने से व्यस्त समय में गति घट सकती है। हालांकि, यह हर केबल कनेक्शन के साथ होना जरूरी नहीं है। यह मानना गलत है कि फाइबर हमेशा महंगा होता है। कीमत इंटरनेट की गति, मासिक योजना, सेवा प्रदाता और अतिरिक्त सुविधाओं पर निर्भर करती है। फाइबर में ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल यानी ओएनटी की जरूरत पड़ सकती है, जबकि केबल में उपयुक्त मॉडेम या राउटर इस्तेमाल होता है। उपकरणों का शुल्क, स्थापना खर्च और सुरक्षा राशि पहले पड़ेंगे। कुछ कंपनियां इंटरनेट के साथ टीवी चैनल या मनोरंजन सेवाएं भी देती हैं। योजना चुनने से पहले देखें कि इनमें से कौन सी सुविधाएं वास्तव में आपके काम की हैं।

अनूपपुर में रेल जनसंवाद या सिर्फ फोटो सेशन, जनता नदारद, अधिकारी करते रहे संवाद

पैन इंडिया रेल जनसंवाद की मंशा पर उठे सवाल, यात्रियों की समस्याओं और जनभागीदारी की अनदेखी का आरोप; अधूरी सुविधाओं पर जवाबदेही तय करने की मांग



न्यूज विंडो

मलखंब में अग्रणी महाविद्यालय का दमदार प्रदर्शन, संभाग स्तरीय स्पर्धा में बना चैंपियन



सागर। भारतीय संस्कृति और पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शासकीय कला एवं वाणिज्य (अग्रणी) महाविद्यालय, सागर में संभाग स्तरीय मलखंब प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्राचार्य प्रो. सरोज गुप्ता के निदेशन में हुई स्पर्धा में मेजबान महाविद्यालय की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियन का खिताब जीता, जबकि शासकीय महाविद्यालय शाहगढ़ की टीम उपविजेता रही। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम तिवारी, जिला उपाध्यक्ष निकेश गुप्ता और क्षेत्रीय खेल संचालक शर्मिला डाबर की उपस्थिति में हुआ। प्राचार्य प्रो. सरोज गुप्ता ने कहा कि मलखंब जैसे पारंपरिक खेल शारीरिक सौष्ठव के साथ मानसिक एकाग्रता, अनुशासन और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता विकसित करते हैं। श्याम तिवारी ने पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने की पहल को सराहनीय बताया, वहीं निकेश गुप्ता ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता में सागर के अग्रणी महाविद्यालय, पीएम श्री शासकीय महाविद्यालय मकरोनिया, शासकीय महाविद्यालय शाहगढ़ और शासकीय कन्या महाविद्यालय सागर की टीमों ने हिस्सा लिया।

नरवाई जलाई तो 15 हजार रुपये तक जुर्माना जबलपुर जिले में 60 दिन के लिए प्रतिबंध



जबलपुर। फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाने वालों पर अब सख्ती होगी। जबलपुर जिले में नरवाई जलाने पर 60 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। अपर जिला दंडाधिकारी नीता राठौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163(2) के तहत यह आदेश जारी किया है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नरवाई जलाने पर जमीन के रकबे के अनुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि वसूली जाएगी। दो एकड़ से कम भूमि पर 2,500 रुपये, दो से पांच एकड़ से कम पर 5,000 रुपये और पांच एकड़ से अधिक भूमि पर 15,000 रुपये प्रति घटना जुर्माना निर्धारित है। आदेश के अनुसार, कंबाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रू मैनेजमेंट सिस्टम, स्ट्रू रीपर या बेल्तर लगाना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर हार्वेस्टर जब्त किया जा सकता है। प्रतिबंध के पालन की जिम्मेदारी कृषि विभाग की सौंपी गई है। ग्राम पंचायत स्तरीय निगरानी समितियां उल्लंघन की रिपोर्ट देंगी। तहसीलदार सुनवाई के बाद सात दिनों में जुर्माने पर निर्णय लेंगे। प्रशासन ने किसानों को जागरूक करने के लिए गांवों में मुनादी कराने के निर्देश भी दिए हैं। नरवाई जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है और मिट्टी की उर्वरता को नुकसान पहुंचता है।

मेट्रो एंकर धार वन मंडल में भर्ती प्रक्रिया शुरू, दस्तावेज जांच, शारीरिक मापदंडों का परीक्षण पूरा, 25 किमी की पैदल चाल से तय होगी चुनौती

वनरक्षक के 7 पदों के लिए 196 अभ्यर्थियों में मुकाबला, 172 पहुंचे मैदान में

धार। दोपहर मेट्रो वनरक्षक भर्ती के तहत धार वन मंडल में सात पदों के लिए अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला शुरू हो गया है। आयोजित शारीरिक परीक्षण में पंजीकृत 196 अभ्यर्थियों में से 172 उपस्थित हुए, जबकि 24 अनुपस्थित रहे। पहले दिन दस्तावेजों की जांच, बायोमेट्रिक सत्यापन और शारीरिक मापदंडों के परीक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई। अब 24 अक्टूबर को होने वाली 25 किलोमीटर की पैदल चाल अभ्यर्थियों की अगली बड़ी परीक्षा होगी। भर्ती में शामिल होने के लिए खरगोन, खंडवा, रतलाम और आलीराजपुर सहित आसपास के जिलों से अभ्यर्थी धार पहुंचे। प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की कमटी निगरानी कर रही है। इसमें वन विभाग के साथ प्रशासन, पुलिस और चिकित्सा



विभाग से जुड़े अधिकारियों की मौजूदगी रखी गई है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत पहले दस्तावेजों की जांच, फिर बायोमेट्रिक सत्यापन और उसके बाद अभ्यर्थियों की ऊंचाई तथा सीने की चौड़ाई मापी गई। पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार आधारित सत्यापन भी किया गया। भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में अभ्यर्थियों को

धार वन मंडल से सलकनपुर तक 25 किलोमीटर की पैदल चाल पूरी करनी होगी। इसमें उनकी शारीरिक क्षमता और सहनशक्ति परखी जाएगी। परीक्षण के दौरान एक गर्भवती महिला अभ्यर्थी का शारीरिक परीक्षण नहीं हो सका। अब पैदल चाल के बाद निर्धारित नियमों के अनुसार चयन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

24 अभ्यार्थी अनपस्थित रहे

वनरक्षक भर्ती के पहले दिन कुल 196 अभ्यर्थियों में से 172 उपस्थित रहे, जबकि 24 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। सात पदों के लिए आयोजित इस प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की पात्रता और शारीरिक मापदंडों की जांच की गई। सबसे पहले दस्तावेजों का सत्यापन किया गया, इसके बाद बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी हुई। फिर अभ्यर्थियों की ऊंचाई और सीने की चौड़ाई मापी गई। पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार आधारित सत्यापन की व्यवस्था भी अपनाई गई। भर्ती में शामिल होने के लिए खरगोन, खंडवा, रतलाम और आलीराजपुर सहित आसपास के जिलों से अभ्यर्थी धार पहुंचे। पूरा प्रक्रिया पर अधिकारियों की विशेष कमटी नजर रख रही है, ताकि निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

25 किमी की पैदल चाल, सहनशक्ति की होगी परीक्षा

भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में 24 अक्टूबर को अभ्यर्थियों को धार वन मंडल से सलकनपुर तक 25 किलोमीटर की पैदल चाल पूरी करनी होगी। यह चरण अभ्यर्थियों की शारीरिक क्षमता और सहनशक्ति परखने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। सात पदों के लिए जारी भर्ती में इस परीक्षा पर सभी की निगाहें टिकी हैं। प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रशासन, पुलिस और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की निगरानी व्यवस्था रखी गई है। पहले दिन एक गर्भवती महिला अभ्यर्थी का शारीरिक परीक्षण नहीं हो सका। आगे की प्रक्रिया निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी। पैदल चाल के परिणाम के बाद चयन प्रक्रिया अगले चरण में बढ़ेगी।

मोतीनगर पुलिस की कार्रवाई, बालाजी नगर और सिंधी कैंप में दबिश

सागर में अवैध पटाखों पर पुलिस का छापा, 10.50 लाख का माल जब्त

सागर। दोपहर मेट्रो

त्योहारों के मद्देनजर अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री के खिलाफ सागर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। थाना मोतीनगर पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में करीब 10 लाख 50 हजार रुपये मूल्य के पटाखे जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निदेशन में की गई इन कार्रवाइयों का उद्देश्य अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। दोनों मामलों में प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

पहली कार्रवाई मोतीनगर थाना क्षेत्र के बालाजी नगर, अंबेडकर वार्ड में की गई। यहां पुलिस ने 23 खाकी कार्टून में रखे करीब 10 लाख रुपये मूल्य के पटाखे जब्त किए। इनमें अनारदाना, फुलझड़ी, सुतली बम, रॉकेट और लड़ियों वाले पटाखे शामिल हैं। इस मामले में सुनील पिता महेश शर्मा (41), निवासी अंबेडकर वार्ड तथा छोट्टू अरविंद पांडा और मौसम शर्मा के विरुद्ध कार्रवाई की गई। पुलिस ने



बालाजी नगर में 23 कार्टून पटाखे मिले

मोतीनगर थाना क्षेत्र के बालाजी नगर स्थित अंबेडकर वार्ड में पुलिस ने दबिश देकर 23 खाकी कार्टून में रखे करीब 10 लाख रुपये मूल्य के पटाखे जब्त किए। जब्त सामग्री में अनारदाना, फुलझड़ी, सुतली बम, रॉकेट और लड़ियों वाले पटाखे सहित विभिन्न किस्मों के आतिशबाजी उत्पाद शामिल हैं। पुलिस ने इस मामले में सुनील पिता महेश शर्मा, उम्र 41 वर्ष, निवासी अंबेडकर वार्ड तथा छोट्टू अरविंद पांडा और मौसम शर्मा के विरुद्ध कार्रवाई की है। प्रकरण अपराध क्रमांक 1311/26 के तहत दर्ज किया गया है।

अपराध क्रमांक 1311/26 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

दूसरी कार्रवाई सिंधी कैंप में बालचंद तलवानी की दुकान पर की गई, जहां से करीब 50 हजार रुपये के विभिन्न प्रकार के पटाखे जब्त किए गए। इस मामले में अपराध क्रमांक 1112/26 के

तहत प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। कार्रवाई के दौरान एसपी अनुराग सुजानिया स्वयं मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। नगर पुलिस अधीक्षक ललित कश्यप, थाना प्रभारी मोतीनगर जसवंत सिंह सहित पुलिस स्टाफ मौजूद रहा।

सिंधी कैंप की दुकान से 50 हजार के पटाखे जब्त

मोतीनगर पुलिस ने दूसरी कार्रवाई सिंधी कैंप में की। यहां निवासी बालचंद तलवानी की दुकान से करीब 50 हजार रुपये मूल्य के पटाखे जब्त किए गए। इनमें अनारदाना, फुलझड़ी, सुतली बम, रॉकेट, लड़ियों वाले पटाखों के पैकेट और अन्य आतिशबाजी सामग्री शामिल है। पुलिस ने अवैध भंडारण एवं विक्रय के संबंध में अपराध क्रमांक 1112/26 के तहत प्रकरण दर्ज किया है और विवेचना जारी है। दोनों कार्रवाइयां पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निदेशन में हुईं। एसपी ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का जायजा लिया। इस दौरान नगर पुलिस अधीक्षक ललित कश्यप, थाना प्रभारी जसवंत सिंह और पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। पुलिस का कहना है कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निगरानी जारी रहेगी।

18 साल से सरपंच, फिर भी FIR के लिए सात घंटे इंतजार, कोतवाली की कार्यप्रणाली पर सवाल

जनपद पंचायत अध्यक्ष के थाने पहुंचने के बाद दर्ज हुई शिकायत

पसला की महिला सरपंच के साथ कथित मारपीट और बिल-वाउचर पर जबरन हस्ताक्षर कराने का मामला

अनूपपुर। दोपहर मेट्रो

जिले की ग्राम पंचायत पसला की महिला सरपंच सन्तरी सिंह के साथ कथित मारपीट और बिल-वाउचर पर जबरन हस्ताक्षर कराने का मामला सामने आया है। घटना के बाद एफआईआर दर्ज कराने के लिए करीब सात घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इस घटनाक्रम ने अनूपपुर सिटी कोतवाली की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, सन्तरी सिंह, पत्नी रोहित सिंह, पसला ग्राम पंचायत की सरपंच हैं और करीब 18 वर्षों से पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उनके साथ हुई कथित घटना के

बाद बड़ी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता थाने पहुंचे। बताया जाता है कि जनपद पंचायत जैतहरी के अध्यक्ष को भी मामले में थाने पहुंचकर बैठना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज की। एक निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि को शिकायत दर्ज कराने के लिए घंटों इंतजार करना पड़े, तो आम नागरिकों की सुनवाई को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। हालांकि, मामले में पुलिस की ओर से देरी के कारणों की स्थिति स्पष्ट होना बाकी है। विवाद की जड़ बिल-वाउचर पर हस्ताक्षर कराने का दबाव बताया जा रहा है। अब जांच में यह स्पष्ट होना जरूरी है कि संबंधित बिल-वाउचर किस कार्य से जुड़े थे, उनमें कितनी राशि थी और विवाद किन परिस्थितियों में हुआ। मामले के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच से ही वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी।

18 साल का प्रतिनिधित्व अब जवाबदेही पर सवाल

ग्राम पंचायत पसला की सरपंच सन्तरी सिंह करीब 18 वर्षों से पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उनके साथ कथित मारपीट के मामले में शिकायत दर्ज कराने के लिए करीब सात घंटे इंतजार की बात सामने आई है। समर्थकों और जनपद पंचायत जैतहरी के अध्यक्ष की मौजूदगी के बाद पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने की जानकारी है। इस घटनाक्रम ने पुलिस की शिकायत सुनने और दर्ज करने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि शिकायत दर्ज करने में देरी क्यों हुई? साथ ही, बिल-वाउचर पर जबरन हस्ताक्षर कराने के आरोपों की भी निष्पक्ष जांच जरूरी है, ताकि घटना की वास्तविक वजह और जिम्मेदारी स्पष्ट हो सके।

जबलपुर : नगर निगम का बाबू 20 हजार लेते रंगे हाथों पकड़ाया

जबलपुर। दोपहर मेट्रो

बैंक लोन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के बदले रिश्तत मांगना कटनी नगर निगम के लिपिक को भारी पड़ गया। लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए नगर निगम की संपदा शाखा में पदस्थ लिपिक आलोक गर्ग को 20 हजार रुपये की रिश्तत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया।

लोकायुक्त एसपी अंजुलता पटले के अनुसार, ट्रांसपोर्टर अशोक कनकने को ट्रांसपोर्ट नगर, पुरैनी में प्लॉट नंबर 137 आवंटित है। यहां निर्माण कार्य कराने के लिए उन्होंने बैंक से ऋण लेने का आवेदन किया था। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऋण स्वीकृति के लिए नगर निगम से एनओसी मांगी थी। एनओसी जारी कराने के लिए अशोक कनकने ने संपदा शाखा में पदस्थ लिपिक आलोक गर्ग से संपर्क किया। आरोप है कि लिपिक ने प्रमाण पत्र जारी



करने के बदले 25 हजार रुपये की रिश्तत मांगी। इससे परेशान होकर ट्रांसपोर्टर ने लोकायुक्त जबलपुर में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत का सत्यापन करने के बाद लोकायुक्त टीम ने जाल बिछाया। शुक्रवार को शिकायतकर्ता ने जैसे ही लिपिक को 20 हजार रुपये दिए, टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। कार्रवाई में रेखा प्रजापति, राहुल गजभिए और शशि मरसकुले सहित अन्य सदस्य शामिल रहे। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

28 अक्टूबर से कुमेड़ी ISBT से दौड़ेंगी अंतर्राज्यीय बसें

इंदौर। लंबे इंतजार के बाद कुमेड़ी अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (ISBT) से 28 अक्टूबर से बसों का संचालन शुरू होगा। यहां से उज्जैन होकर राजस्थान, गुजरात और दिल्ली जाने वाली बसें संचालित होंगी। हालांकि, बसों को ISBT पहुंचने के लिए रिंग रोड का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। आरटीओ प्रदेप शर्मा ने बस संचालकों के साथ बैठक कर संचालन की व्यवस्था तय की। बसों को तीन इमली से बायपास होकर रेडिसन चौराहा पहुंचना होगा। यातायात पुलिस ने विजय नगर रोड जाने की स्वीकृति दी है। नए बस स्टैंड से संचालन शुरू होने पर यात्रियों को सुविधा मिलने की उम्मीद है।

30 स्वर्ण, 35 रजत और 49 कांस्य जीतकर तोड़ा पिछला रिकॉर्ड, तीरंदाजी, निशानेबाजी में चमके भारतीय खिलाड़ी

एशियन पैरा गेम्स में भारत का धमाका, 114 पदकों के साथ रचा इतिहास

आइची-नागोया, एजेंसी

जापान के आइची-नागोया में आयोजित एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से इतिहास रच दिया। भारत ने प्रतियोगिता में 30 स्वर्ण, 35 रजत और 49 कांस्य सहित कुल 114 पदक जीतकर अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही भारतीय दल ने चीन के हांग्झू में 2023 में बनाए गए 108 पदकों के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। खास बात यह रही कि पिछली बार की तुलना में लगभग आधे खिलाड़ियों के दल के बावजूद भारत ने अधिक पदक जीतकर अपनी ताकत साबित की। भारत ने प्रतियोगिता में चौथा स्थान हासिल किया।

भारत ने इस बार एशियन पैरा गेम्स में 168 खिलाड़ियों का दल भेजा था। इसके बावजूद खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में दमदार प्रदर्शन करते हुए पदकों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की। एथलेटिक्स में भारत की पदक तालिका में सबसे बड़ा योगदान दिया। इस स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल

65 पदक जीते, जो 2023 के मुकाबले 12 अधिक हैं। बैडमिंटन, तीरंदाजी और निशानेबाजी में भी खिलाड़ियों ने कई स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। प्रतियोगिता के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने विश्व रिकॉर्ड और खेलों के रिकॉर्ड भी बनाए।

भारतीय तीरंदाज हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने पुरुष रिकर्व युगल स्पर्धा के फाइनल में चीन को 5-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं, भावना चौधरी और पूजा जात्यान की जोड़ी को महिला रिकर्व युगल के फाइनल में हार के बाद रजत पदक मिला। निशानेबाज मोना अग्रवाल ने भी अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1 स्पर्धा में 357.5 अंक हासिल कर विश्व रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन एसएच1 स्पर्धा में भी स्वर्ण जीतकर दोहरी सफलता हासिल की। मोना को निषाद कुमार के साथ समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है।



भाला फेंक में भारतीय खिलाड़ियों का क्लीन स्वीप

भाला फेंक में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही स्पर्धा के तीनों पदक अपने नाम किए। दो बार के पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल ने पुरुषों की संयुक्त एफ42-44/61-64 स्पर्धा में 72.46 मीटर दूर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। महेंद्र गुर्जर ने 59.03 मीटर के प्रदर्शन के साथ रजत, जबकि संदीप संजय सरगार ने 64.48 मीटर भाला फेंककर कांस्य पदक हासिल किया। हनी ने पुरुषों की भाला फेंक एफ37/38 स्पर्धा में 60.49 मीटर का विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। वहीं, प्रणव सूरमा ने पुरुषों की क्लब शो एफ51 स्पर्धा में 32.87 मीटर के खेलों के रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। धरमवीर को इसी स्पर्धा में कांस्य मिला।

दौड़ और लंबी कूद में भी चमके खिलाड़ी

भारत के संदीप ने पुरुषों की 400 मीटर टी64 स्पर्धा में 52.28 सेकंड का समय निकालकर विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। अजय कुमार ने 53.61 सेकंड में दौड़ पूरी कर कांस्य पदक हासिल किया और खेलों का रिकॉर्ड बनाया। निमिषा चक्रगुलपरबिल ने महिला लंबी कूद टी47, जबकि प्रमोद बिजारनिया ने पुरुषों की 1500 मीटर टी46 स्पर्धा में रजत पदक जीता। पैरा बैडमिंटन में थुलासिमथी मुरुगेसन और मानसी गिरिशचंद्र जोशी ने महिला युगल एसएल3-एसयू5 वर्ग के फाइनल में चीन की जोड़ी को 21-16, 21-13 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में नितेश कुमार और नवीन शिवकुमार ने भी स्वर्ण पदक हासिल किए।

तैराकी में भी भारत ने दिखाई ताकत

भारतीय तैराकी दल ने कुल 11 पदक जीतकर उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया। हिमांशु नंदल ने पुरुषों की 100 मीटर फ्रीस्टाइल एस11 स्पर्धा में एक मिनट 5.90 सेकंड का समय निकालकर कांस्य पदक जीता। इससे पहले वह 400 मीटर फ्रीस्टाइल और 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक में भी कांस्य पदक जीत चुके थे। इस तरह उन्होंने प्रतियोगिता में तीन पदक अपने नाम किए।

कप्तान पैट कर्मिस ने दिए बड़े बदलाव के संकेत

साउथ अफ्रीका से हार के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम में खलबली

गकेबरह, एजेंसी

साउथ अफ्रीका के हाथों टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में पारी और 31 रनों से हार झेलने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम पर सवाल खड़े हो गए हैं। कप्तान पैट कर्मिस ने स्वीकार किया कि टीम मैनेजमेंट को अब प्लेइंग इलेवन पर नए सिरे से विचार करना होगा। 27 अक्टूबर से केपटाउन में शुरू होने वाले निर्णायक टेस्ट के लिए कैमरन ग्रीन और जोश इंगिस को उतारलब्धता भी चयन को प्रभावित कर सकती है।

गकेबरह टेस्ट मैच में फॉलोऑन खेलने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरी पारी में 295 रनों पर सिमट गई। मार्नस लाबुशेन 39 रन बनाकर आउट हुए, जबकि निक मैडिनसन और ब्यू वेबस्टर बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। मैडिनसन ने पहली पारी में शून्य और दूसरी इनिंग्स में आठ रन बनाए। वहीं वेबस्टर के बल्ले से 13 और 8 रन निकले। लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को एक और मौका देने



या उनकी जगह नए खिलाड़ियों को उतारने पर ऑस्ट्रेलियाई टीम प्रबंधन को फैसला करना होगा। कर्मिस ने कहा, हमेशा यह चुनौती रहती है कि किसी खिलाड़ी को एक और मैच दिया जाए या बदलाव करने का यही सही समय है। अगले कुछ दिनों में इसी पर चर्चा होगी। उन्होंने यह भी बताया कि कैमरन ग्रीन और जोश इंगिस तीसरे टेस्ट के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। पैट कर्मिस के मुताबिक, टीम कॉम्बिनेशन पर विचार करते समय दोनों खिलाड़ियों के नाम चर्चा में आएंगे।

पहलह्य टेस्ट में कंगारुओं को मिली थी जीत

कंगारु टीम ने पहला टेस्ट 214 रनों से जीता था। उस मुकाबले में मैट रेनशॉ ने 10 साल बाद अपना पहला टेस्ट शतक लगाया, लेकिन पैट कर्मिस ने माना कि टीम की बल्लेबाजी तब भी उम्मीद के मुताबिक नहीं थी। उन्होंने कहा, रेनशॉ ने डरबन में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन मुझे लगता है कि खासकर बल्लेबाजी में हम अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर नहीं थे। हमारे बल्लेबाजों की क्षमता और उनके अपने मानकों को देखते हुए, हम उम्मीद से कम रन बना रहे हैं। पैट कर्मिस ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के पास केपटाउन टेस्ट से पहले तैयारी और अपनी गलतियों की समीक्षा करने के लिए कुछ दिन हैं।

मनोरंजन

बॉलीवुड का कोना

गुंबई। मनोरंजन के साथ बच्चों की कल्पनाशक्ति और जिज्ञासा को बढ़ावा देने वाली फिल्मों की जरूरत पर अभिनेत्री रसिका दुग्गल ने जोर दिया है। उनकी आगामी फिल्म ‘लिटिल थॉमस’ इसी सोच को पढ़े पर उतारने की कोशिश करती है। अभिनेत्री का मानना है कि बच्चों के लिए ऐसी कहानियां बनाई जानी चाहिए, जिनमें वे अपने अनुभवों और भावनाओं को पहचान सकें और अपनी दुनिया को नए नजरिए से देख सकें।

बच्चों की कल्पनाओं को नई उड़ान देगी ‘लिटिल थॉमस’, रसिका दुग्गल बोलीं—

ऐसी फिल्म में बेहद जरूरी

रसिका दुग्गल ने कहा कि सिनेमा बच्चों की दुनिया को बड़ा करने और उनकी कल्पनाशक्ति को विकसित करने का प्रभावशाली माध्यम है। बचपन में देखी गई फिल्मों और कहानियां बड़े होने पर भी हमारी सोच को प्रभावित करती हैं। इसलिए बच्चों के लिए ऐसी फिल्में जरूरी हैं, जो उनकी जिज्ञासा को दबाने के बजाय उसे प्रोत्साहित करें। अभिनेत्री के मुताबिक, बच्चों का मनोरंजन करने के लिए कहानी का हल्का-फुल्का होना ही जरूरी नहीं है। गंभीर भावनाओं और वास्तविक अनुभवों को भी रोचक अंदाज में पेश

किया जा सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ज्यादा से ज्यादा फिल्ममेकर बच्चों के नजरिए से कहानियां कहने का प्रयास करेंगे। कोशल ओझा के निर्देशन में बनी ‘लिटिल थॉमस’ में रसिका दुग्गल जेसी मिरांडा की भूमिका निभा रही हैं। जेसी एक ऐसी मां हैं, जिनकी जिंदगी अपने परिवार, बेकरी और संगीत के प्रति प्रेम के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में गुलशन देवैया और बाल कलाकार हर्दाश पारेख भी अहम भूमिकाओं में हैं। कहानी 1990 के दशक के गोवा में रहने वाले सात वर्षीय थॉमस और उसके परिवार के जीवन के उतार-चढ़ाव को दिखाती है।

बचपन के सवालों से बुनी गई कहानी

‘लिटिल थॉमस’ की खासियत दुनिया को एक बच्चे की नजर से देखने का इसका अंदाज है। कहानी में थॉमस की जिज्ञासाएं, उसके मासूम सवाल और उनके जवाब जानने की जिद कई दिलचस्प परिस्थितियों को जन्म देती हैं। पारिवारिक रिश्तों और रोजमर्रा की घटनाओं के जरिए फिल्म बचपन की सहजता को सामने लाती है। फिल्म का परिवेश मालगुडी डेज और ररिकन बॉन्ड की कहानियों की याद दिलाने वाला बताया गया है, जहां छोटे-छोटे अनुभवों में जीवन के बड़े अर्थ छिपे होते हैं।



मेट्रो बाजार

नई दिल्ली। भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के वैश्विक क्षमता केंद्रों में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। वर्ष 2026 में इन केंद्रों में नौकरी के अवसर करीब 93 प्रतिशत बढ़कर 67,000 तक पहुंचने का अनुमान है। खास बात यह है कि कंपनियां नए उम्मीदवारों के मुकाबले 3 से 12 वर्ष का अनुभव रखने वाले पेशेवरों को प्राथमिकता दे रही हैं। क्रेस कॉर्प की रिपोर्ट के अनुसार,

भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नौकरियों का उछाल, 67 हजार पदों पर भर्ती का अनुमान

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आंकड़ा विश्लेषण, चिकित्सकीय अनुसंधान और नियामक मामलों में भर्ती की मांग तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के वैश्विक क्षमता केंद्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता सबसे तेजी से विस्तार करने वाली तकनीक बनेगी। फिलहाल करीब 60 प्रतिशत केंद्रों में इसका इस्तेमाल हो रहा है, जो 2030 तक बढ़कर 80 से 90 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। चिकित्सकीय प्रक्रियाओं, अनुसंधान एवं विकास, संचालन और उत्पाद विकास में इसके बढ़ते

उपयोग से विशेषज्ञ पेशेवरों की मांग भी बढ़ेगी। क्रस आईटी सॉल्यूशंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कपिल जोशी के अनुसार, पिछले साल नियुक्तियां लगभग दोगुनी हुईं, जबकि 2023 के बाद से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आंकड़ा संबंधी विशेषज्ञों की मांग करीब 150 प्रतिशत बढ़ी है। हालांकि, योग्य पेशेवरों की कमी कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में फिलहाल 155 वैश्विक क्षमता केंद्र सक्रिय हैं, जिनमें करीब 3.2 लाख पेशेवर काम कर रहे हैं।

बर्लिन से टोरंटो तक श्वेता त्रिपाठी की उड़ान!

अभिनेत्री श्वेता त्रिपाठी इन दिनों अपनी फिल्म ‘मुझे जान ना कहो मेरी जान’ को अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों और बाजारों तक पहुंचाने में जुटी हैं। बतौर प्रोड्यूसर उनकी पहली फीचर फिल्म ने इस साल की शुरुआत में बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से अपना सफर शुरू किया था और अब वह टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 तक पहुंच गई है। श्वेता के लिए यह उपलब्धि खास है, क्योंकि निर्माता के रूप में इस फिल्म ने उन्हें कहानी कहने के साथ-साथ उसे दर्शकों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को भी करीब से समझने का मौका दिया है। श्वेता त्रिपाठी का कहना है कि एक

पहली प्रोड्यूसर की हुई फिल्म से अंतरराष्ट्रीय मंच पर बनाई पहचान

अभिनेत्री और निर्माता के रूप में कहानी को देखने का नजरिया अलग होता है। अभिनेत्री के तौर पर उनका ध्यान किरदार को पढ़ें पर जीवंत करने पर रहता है, जबकि निर्माता के रूप में फिल्म के भविष्य, उसके दर्शकों और उससे शुरू होने वाली बातचीत के बारे में भी सोचना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जिस फिल्म पर आपको भरोसा हो, उसे अंतरराष्ट्रीय मंच तक ले जाना अपने आप में खास अनुभव है। बर्लिन से टोरंटो तक का सफर उनके लिए सीखने और फिल्म को नए दर्शकों के



सामने पेश करने का अवसर रहा है। श्वेता के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय फिल्म

समारोह और मार्केट दुनिया भर के फिल्मकारों, निर्माताओं और सिनेमा से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाते हैं। यहां फिल्मों के लिए नए अवसर तलाशने और उन्हें अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंचाने की संभावनाएं बनती हैं। उन्होंने कहा कि बतौर निर्माता उनकी जिम्मेदारी सिर्फ फिल्म तैयार होने तक सीमित नहीं है। यह समझना भी जरूरी है कि कहानी किन लोगों तक पहुंचेगी और दर्शकों के बीच किस तरह की चर्चा को जन्म दे सकती है।

अक्टूबर में भारत की कारोबारी गतिविधियां चार महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची

नई दिल्ली। अक्टूबर में भारत के निजी क्षेत्र की कारोबारी गतिविधियों (बिजनेस एक्टिविटी) में जोरदार तेजी दर्ज की गई और यह चार महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। एचएसबीसी द्वारा जारी फ्लैश पीएमआई आंकड़ों के अनुसार, घरेलू मांग के साथ-साथ विदेशी बाजारों से मिले मजबूत ऑर्डरों ने विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों को गति दी है। साथ ही महंगाई से जुड़े दबावों में भी नरमी देखने को मिली है। एचएसबीसी फ्लैश इंडिया कंपोजिट आउटपुट इंडेक्स, जो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की संयुक्त गतिविधियों को मापता है, सितंबर के 55.9 से बढ़कर अक्टूबर में 56.7 पर पहुंच गया। 50 से ऊपर का स्तर आर्थिक गतिविधियों के विस्तार का संकेत माना जाता है। यह जून के बाद कारोबारी गतिविधियों की सबसे तेज वृद्धि है। आंकड़ों के अनुसार, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की

कंपनियों ने बाजार की स्थितियों में सुधार और नए ऑर्डरों में बढ़ोतरी की जानकारी दी। विदेशी मांग भी मजबूत रही और निर्यात ऑर्डरों में पिछले छह महीनों की सबसे तेज वृद्धि दर्ज की गई। एचएसबीसी की मुख्य भारत अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन और नए ऑर्डरों की वृद्धि सितंबर के स्तर के आसपास बनी रही, लेकिन इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण पहलू निर्यात मांग में आई तेजी रही। उन्होंने कहा कि जून 2025 के बाद पहली बार निर्यात ऑर्डरों में इतनी मजबूत वृद्धि देखने को मिली है। उन्होंने बताया कि बढ़ती मांग को देखते हुए निर्माताओं ने कच्चे माल और तैयार माल दोनों का भंडारण बढ़ाया है। इसके साथ ही उत्पादन लागत और बिक्री मूल्य पर पड़ने वाला दबाव भी लगातार कम हो रहा है, जो महंगाई के मोर्चे पर राहत का संकेत है।





समुद्र मंथन योजना.... गहरे पानी में तेल खोजेंगी कंपनियां

सरकार का 84084 करोड़ का मेगा प्लान

इन क्षेत्रों में ड्रिलिंग खर्च बहुत अधिक होता है और भूगर्भीय संभावनाएं अनिश्चित होती हैं, जिससे निवेश करने में कंपनियां हिचकिचाती हैं।

योजना का लक्ष्य ऊर्जा आयात निर्भरता घटना

योजना का लक्ष्य हाइड्रोकार्बन के आयात पर भारत की भारी निर्भरता को कम करना है। यह योजना वित्त वर्ष 2030-31 तक चलेगी। इसमें वित्त वर्ष 2026-27 को

तैयारी के वर्ष के रूप में रखा गया है, जबकि वित्त वर्ष 2027-28 से 2030-31 तक की अवधि को 'चरण-1' माना जाएगा, जिसमें खर्च किया जाएगा। पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल ने दिशानिर्देशों की प्रस्तावना में इस योजना को हाल के समय में शुरू की गई तेल और गैस क्षेत्र की सबसे महत्वाकांक्षी पहल बताया और कहा कि इससे भारत के भंडार में 600 मिलियन टन से अधिक तेल के बराबर की वृद्धि हो सकती है।

ओमान और इराक से भी आयात प्रभावित

ईरान ने पाकिस्तान की एलपीजी सप्लाई रोकी: एक सिलेंडर कीमत हुई 7000 रुपए

इस्लामाबाद/तेहरान, एजेंसी

ईरान ने पाकिस्तान को एलपीजी की सप्लाई रोक दी है। पाकिस्तान अपनी कुल एलपीजी जरूरत का करीब 50% हिस्सा ईरान से आयात करता है। ऐसे में सप्लाई रुकने से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। 12 किलो के सिलेंडर की कीमत कुछ ही दिनों में 4500 पाकिस्तानी रुपए से बढ़कर 7000 रुपए हो गई है। यानी दाम 2500 रुपए बढ़ गए हैं।

सीमा बंद होने से रुकी गैस की सप्लाई

पाकिस्तान और ईरान के बीच गब्द-रिमदान और तफान की दो प्रमुख सीमा चौकियां 17 अक्टूबर को बंद कर दी गई थीं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की सरकार ने सुरक्षा चिंताओं और तस्करों रोकने को इसकी वजह बताया, जबकि ईरान ने तकनीकी दिक्कतों का हवाला दिया। पाकिस्तान एलपीजी एसोसिएशन के मुताबिक, ईरान से रोजाना करीब 7000 मीट्रिक टन एलपीजी पाकिस्तान आती है। ग्वादर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड



इंडस्ट्री के पूर्व अध्यक्ष शम्सुल हक ने बताया कि अकेले गब्द-रिमदान सीमा से हर दिन 4000 टन से ज्यादा गैस आती है। फिलहाल यह सप्लाई रुकी हुई है। पाकिस्तान अपनी एलपीजी जरूरत का करीब 70% हिस्सा विदेशों से आयात करता है। ईरान के अलावा इराक और ओमान से भी गैस आती है। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक के मुताबिक, देश में हर दिन करीब 6500 से 7000 टन एलपीजी की जरूरत होती है। इसमें से 2000 से 2500 टन गैस देश में तैयार होती है।

ट्रेलर से भिड़ी मिनी बस, नासिक के 3 श्रद्धालुओं की मौत और 25 घायल

जयपुर। जयपुर से लगभग 20-30 किमी दूर बगरूम में नेशनल हाईवे-48 पर मिनी बस की टक्कर ट्रेलर से हो गई। इस हादसे में तीन श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं करीब 25 लोग घायल हैं। बस खाटू श्याम से सालासर की ओर जा रही थी। बस में कुल 30 यात्री सवार थे। ये लोग नासिक के रहने वाले हैं। 7 लोगों को जयपुर के SMS अस्पताल रेफर किया गया है। मिनी बस और ट्रेलर की टक्कर के मामले में, जांच अधिकारी लालाराम ने बताया, 'रात करीब 2:00 बजे हमें पुलिस मित्र से सूचना मिली कि एक गंभीर हादसा हुआ है। मैंने तुरंत पेट्रोल यूनिट को अलर्ट किया और मौके पर पहुंचा।'

भाग गया बस का ड्राइवर

जांच अधिकारी लालाराम ने कहा, 'यह हादसा तब हुआ जब एक मिनी-बस ने दूसरी गाड़ी को



ओवरटेक करने की कोशिश की और उससे टकरा गई। ड्राइवर मौके पर नहीं मिला। यात्रियों ने बताया कि वह गाड़ी से कूदकर भाग गया था।' अधिकारी ने आगे बताया, '3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उनके शवों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। 25 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 7 लोगों को जयपुर के स्क्स अस्पताल रेफर किया गया। बस खाटू श्याम से सालासर की ओर जा रही थी। ये लोग नासिक के रहने वाले हैं।'

न्यूज विंडो

मुंबई में जैश-ए-मोहम्मद से कनेक्शन के आरोप में युवक गिरफ्तार

मुंबई। मुंबई एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने माहिम से आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से कनेक्शन के आरोप में 33 साल के मोहम्मद हसन अबू सरमद अख्तर को गिरफ्तार किया है। आरोपी बिहार का रहने वाला है। वह मुंबई में रैपिडो ड्राइवर के तौर पर काम करता था। झूसे के मुताबिक, आरोपी के मोबाइल फोन की जांच में भड़काऊ पोस्ट और मसूद अजहर के ऑडियो क्लिप मिले हैं। अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी की सोशल मीडिया गतिविधियों और एक टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े सुरागों के आधार पर मामला सामने आया। पुलिस का आरोप है कि वह सोशल मीडिया पर जैश-ए-मोहम्मद को बढ़ावा देने वाली सामग्री पोस्ट करता था। जांच एजेंसी यह भी पता लगा रही है कि आरोपी के पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों से संपर्क थे या नहीं।

पुणे के स्कूल में 9वीं की छात्रा पर चाकू से हमला, आरोपी छात्र गिरफ्तार

पुणे। महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक 9वीं की एक छात्रा पर उसके क्लासमेट ने स्कूल के अंदर चाकू से हमला कर दिया। घटना शुक्रवार दोपहर करीब 2:15 बजे महालुगे गांव के स्कूल में हुई। छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक, उसकी हालत स्थिर है। पुलिस के अनुसार, स्कूल के छात्र 17 और 18 अक्टूबर को सतारा जिले के पंचगनी और महाबलेश्वर घूमने गए थे। इस दौरान एक कार्यक्रम में लड़कियों के डॉस का वीडियो बनाया गया था। आरोप है कि 9वीं में पढ़ने वाले छात्र ने यह वीडियो इंस्टाग्राम पर डाल दिया। इसे लेकर छात्रों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद उसने वीडियो हटा दिया। पुलिस को शक है कि इसी विवाद से नाराज होकर छात्र ने छात्रा पर चाकू से हमला किया। पुलिस ने छात्रा का बयान दर्ज कर लिया है और आरोपी छात्र को हिरासत में ले लिया है।

राजस्थान और हरियाणा में ओले गिरे: तमिलनाडु में आंधी-तूफान जारी; यूपी-बिहार में बारिश का अलर्ट



जयपुर/चेन्नई। राजस्थान के 7 जिलों में शनिवार को तेज बारिश का यलो अलर्ट है। अलवर में तूफान के साथ बारिश और ओले भी गिरे। वहीं, हरियाणा के चरखी दादरी और रेवाड़ी में शुक्रवार को बारिश के साथ ओले गिरे।

तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आंधी-बारिश हो रही है और आगे भी भारी बारिश की आशंका है। मदुरै में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में पानी भरने लगा है। वहीं, बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बन सकता है, इससे बिहार और यूपी के पूर्वी हिस्से में 28 अक्टूबर से भारी बारिश हो सकती है।
उत्तराखंड: ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार- उत्तराखंड के 7 जिलों में आज बारिश की संभावना है। इनमें देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ शामिल हैं। 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं। वहीं, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत और पौड़ी के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने की संभावना है।

मेट्रो एंकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक्स अकाउंट एडमिन के खिलाफ रद्द की एफआईआर

सोशल मीडिया पर खबर शेयर करना सांप्रदायिक अपराध नहीं

बेंगलुरु, एजेंसी

कर्नाटक हाई कोर्ट ने कर्नाटक पोर्टफोलियो नाम के सोशल मीडिया अकाउंट के एडमिन संदीप कुमार के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द कर दिया है। संदीप कुमार पर पुत्तूर में छह युवकों द्वारा एक महिला को चाकू दिखाकर धमकाने की घटना से जुड़ी एक रिपोर्ट को रीपोस्ट करने का आरोप था।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अदालत ने माना कि लगाए गए आरोपों से ऐसा कोई अपराध नहीं बनता, जिसमें समुदायों के बीच दुश्मनी या नफरत फैलाने के इरादे से झूठी जानकारी या अफवाहें फैलाई गई हों। अदालत ने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर आपराधिक मामले दर्ज करने के चलन, एक ही घटना पर कई एफआईआर दर्ज करने और पुलिस की शक्तियों के मनमाने इस्तेमाल को रोकने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए।



'यह एक गंभीर मामला था'

अदालत ने टिप्पणी की, 'याचिकाकर्ता द्वारा री-पोस्ट की गई घटना कोई इकलौती या मनगढ़ंत घटना नहीं है। यह एक गंभीर मामला था, जिसमें छह युवकों ने एक समूह बनाया, अपनी थार एसयूवी से एक महिला का पीछा किया और उसे बार-बार धमकाया।' अदालत ने कहा कि कुमार ने केवल कानून-व्यवस्था सवालों के घेरे में जैसे शब्द पोस्ट किए थे। अदालत ने यह भी गौर किया कि इस घटना के संबंध में उसी पुलिस थाने में सात मामले दर्ज किए गए थे। अदालत ने पाया कि न तो शिकायत में और न ही कुमार की पोस्ट में किसी धार्मिक समूह का नाम लिया गया था और न ही इससे सांप्रदायिक अशांति फैलाने के किसी इरादे का संकेत मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि इस अपराध के लिए कुछ जरूरी तत्वों का होना आवश्यक है, जिसमें समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने का इरादा भी शामिल है। अदालत ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए मिले संवैधानिक संरक्षण पर भी जोर दिया।

अदालत ने पुलिस के लिए जारी किए निर्देश

जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए 16 अक्टूबर को यह आदेश सुनाया। उनकी ओर से अधिवक्ता गिरीश भारद्वाज पेश हुए। अदालत ने कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक को निर्देश दिया कि वे अदालत के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। दिशा-निर्देशों के तहत अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि वे सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े मामलों में यह जांचें कि क्या कथित अपराध के लिए जरूरी तत्व मौजूद हैं या नहीं। अदालत ने पुलिस से कहा कि वे एक ही घटना से जुड़ी लगातार आ रही शिकायतों की बारीकी से जांच करें। केवल इसलिए नए मामले दर्ज न करें क्योंकि शिकायतकर्ता अलग-अलग हैं, जब तक कि कोई अलग अपराध सामने न आए।